हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 185 बेमेतरा, बुधवार 25 फरवरी 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

बजट 2026-27: ज्ञान गति के बाद अब संकल्प का बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खोला पिटारा, बस्तर से लेकर सरगुजा तक लगाई सौगातों की झड़ी

साय सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये से विकास के संकल्प का बजट पेश किया

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। यह बजट GYAN और GATI के बाद अब 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का 'SANKALP' बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरगुजा तक सौगातों की झड़ी लगा दी। बजट में प्रत्येक समाज के साथ-साथ युवाओं से लेकर महिलाओं-बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

मुख्यमंत्री साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने वित्त मंत्री को आगामी बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं, सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प को यह बजट और अधिक सशक्त आधार प्रदान करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण तथा वित्त सचिव मुकेश बंसल उपस्थित थे।

प्रदेश के विकास को नई गति देगा बजट : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में प्रस्तुत होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विज़न को नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

बजट की महत्वपूर्ण बातें एक नजर में

- बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी। दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती। बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान। बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान। बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज। आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दूरुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे। जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा तिबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा। राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होगा। कांकेर, कोरवा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा। 206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। रायपुर में खाद लैब का होगा निर्माण। जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।

रानी दुर्गावती योजना का एलान, बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख मिलेंगे

वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना का भी एलान किया। इस योजना के तहत बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार के बजट में मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चौधरी ने कहा कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। औद्योगिक विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भरता व समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की है। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

'सेवा तीर्थ' में पहली बार बैठा मोदी मंत्रिमंडल, नये कार्यालय को बताया देश के नवनिर्माण की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाल्गुन मास की शुक्ल अष्ठमी, मंगलवार को पहली बार यहां नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय भवन 'सेवा तीर्थ' में अपनी पहली बैठक में 'सेवा संकल्प' प्रस्ताव पारित किया और इसे भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ बताया। इस प्रस्ताव में पिछले एक दशक की उपलब्धियों और सुधारों को गिनाते हुए संकल्प व्यक्त किया गया है कि यह सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए भारत को निकट भविष्य में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी।

प्रस्ताव में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति मंत्रिमंडल की प्रतिबद्धता और समर्पण भी व्यक्त किया गया है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ' सेवा संकल्प' में कहा गया है, युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत् 1947, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष..अष्टमी के दिन...24 फरवरी, 2026 को, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में, नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। नये भवन को नये भारत के निर्माण की अभिव्यक्ति बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, 'यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामर्थ्य अनंत हो। आज यह सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा। नये प्रधानमंत्री कार्यालय के स्थान के अंग्रेजों के राज के दौर के बैरक वाले इतिहास को याद करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा हमला किया और कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता नहीं बल्कि मोदी खुद डरपोक हैं जो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से भी

डरते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर किसानों का नुकसान किया है और उसके खिलाफ जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डराने के लिए गिरफ्तार किया जाता है लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है जिसके कारण मोदी जी के प्रति लोगों में भारी रोष है। ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। नाक रगड़कर उनकी सारी शर्तों को मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया।

राहुल गांधी यूथ कांग्रेस प्रमुख की गिरफ्तारी पर भड़के

कहा- दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सरकारी तानाशाही और कायरता

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का सबूत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा।%यह मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस (युवा कांग्रेस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका के साथ डील के दौरान भारत के हितों से समझौता किया गया है। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और इंडियन यूथ कांग्रेस के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।

भीषण हादसा

ट्रेलर व ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में चालक की जलकर मौत

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार की सुबह हुए एक भीषण हादसे में दो ट्रके जलकर खाक हो गई जबकि एक ट्रक के ड्राइवर की आग में जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना कोरबा जिले की मोरगा पुलिस चौकी क्षेत्र में केंदई गांव के पास नेशनल हाईवे 130 पर हुई है। इनमें से एक ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था जो बलौदा बाजार से अंबिकापुर की ओर जा रही थी, जबकि दूसरे ट्रक में कोयला था जो अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर कोरबा जिले के सीमा क्षेत्र में अनेक अंधे मोड है, जिनमें आए दिन बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले सप्ताह भी मड़ई के पास अंधे मोड़ में एक ट्रक और

एक पिकअप के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई थी जिसमे ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर की मौत हो गई थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस सड़क का निर्माण किया तब ऐसे ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। हाईवे के एक बड़े हिस्से में डिवाइडर का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण भी मोड में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। कोरबा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रति उदासीन बने हुए हैं।

दुर्घटना की सूचना पाकर मोरगा चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मोरगा चौकी प्रभारी मनकू राम मरकाम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सुबह मड़ई के पास झरना अंधे मोड़ में दो ट्रकों में आमने सामने से टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया था जिसकी आग से जलकर मौत हो गई। एक ड्राइवर सुरक्षित है। मामले की विवेचना जारी है।

बंगाल के सीमावर्ती जिलों में एसआईआर जांच से पहले न्यायिक अधिकारियों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

कोलकाता। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को ओडिशा, बिहार और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से जिस दिन न्यायिक अधिकारियों की तैनाती कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, उसी दिन भारत-बंगलादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के चार जिलों में तैनात न्यायिक अधिकारियों ने सुरक्षा में चूक की सूचना देते हुए अतिरिक्त सुरक्षा की औपचारिक मांग की है।

बंगलादेश के साथ लंबी सीमा साझा करने वाले मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में तैनात न्यायिक अधिकारियों ने 'तार्किक विसंगति' श्रेणी के तहत चिह्नित मतदाताओं के दस्तावेजों के निस्तारण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा हमले की आशंका जताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है।

पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सोमवार से चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में तार्किक विसंगति श्रेणी के अंतर्गत चिह्नित मतदाताओं के दस्तावेजों की न्यायिक जांच शुरू हो गयी है, जिसमें सत्यापन प्रक्रिया पर न्यायिक निगरानी अनिवार्य की गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा जतायी गयी चिंताओं का संज्ञान लिया है और राज्य पुलिस प्रशासन को व्यापक सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं, ताकि जांच प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल सके। अधिकारियों के अनुसार, राज्यभर में न्यायिक जांच के लिए भेजे गये लगभग 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों में सबसे अधिक संख्या मुर्शिदाबाद जिले से संबंधित है।

हालांकि आयोग ने अब तक जिला-वार आंकड़े आधिकारिक रूप से जारी नहीं किये हैं।

नियद नेल्लानार के 222 गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश

बरसात से पहले निर्माण पूर्ण करने पर जोर, जनगणना की तैयारियां समयबद्ध हों

बीजापुर/मूक पत्रिका

साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर संबित मिश्रा ने विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत चिन्हित 222 गांवों में विकास कार्यों की गति तेज की जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्य हर हाल में बरसात से पहले पूरे किए जाएं ताकि ग्रामीणों को समय पर लाभ मिल सके।बैठक में आगामी जनगणना के प्रथम चरण की तैयारियों पर विशेष फोकस किया गया। कलेक्टर ने कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारण, प्रशिक्षण और आवश्यक व्यवस्थाएं तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते खोलने अभियान चलाने के निर्देश - कलेक्टर ने बैंक खाता विहीन तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते अभियान के रूप में खोलने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र संग्राहकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें भुगतान सीधे खाते में मिल सके। साथ ही व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र के लंबित प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर शीघ्र बैठक आयोजित करने को कहा गया।

आदर्श गांवों में अधोसंरचना कार्यों पर विशेष जोर -नियद नेल्लानार योजना के तहत संचालित सैचुरेशन शिविर सर्वे की समीक्षा के दौरान कावंड़गांव, पालनार, मुतवेंडी, बेलनार, कोण्डापल्ली और चिल्लामरका सहित अन्य आदर्श गांवों में अधोसंरचना निर्माण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि सड़क, भवन और अन्य आधारभूत कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

सुदूर गांवों तक राशन पहुंचाने व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए सुदूर और अंदरुनी गांवों तक ट्रैक्टर के माध्यम से राशन पहुंचाने की व्यवस्था को और विस्तार देने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने ऐसे गांवों की संख्या बढ़ाने को कहा, जहां परिवहन सुविधा सीमित है, ताकि कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित न रहे।

बीजापुर एक्सप्रेस बस संचालन में लापरवाही पर सख्ती -जिला प्रशासन द्वारा संचालित बीजापुर एक्सप्रेस बसों के संचालन में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित संचालकों को तत्काल हटाकर नए संचालक नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों की सुविधा से समझौता नहीं किया जाएगा।

अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर -बैठक में जल जीवन मिशन, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी आवश्यक सेवाएं ग्रामीणों को सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने को कहा गया।आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों के आवश्यक दस्तावेज शीघ्र तैयार करने तथा शासन की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में नम्रता चौबे, भूपेन्द्र अग्रवाल, जागेश्वर कौशल सहित जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नगरीय निकायों के सीएमओ

छत्तीसगढ़ संकल्प बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : नीतू कोठारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रदेश महिला मोर्चा की सोशल मीडिया सह प्रभारी एवं नगर पालिका बेमेतरा की पार्षद नीतू कोठारी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत सछत्तीसगढ़ढ्ढस्ह्यस्रछ्वबजट का स्वागत करते हुए इसे जनकल्याण और सर्वांगीण विकास का बजट बताया है।उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास, पारदर्शी शासन और आम जनता के हितों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रावधान अत्यंत सराहनीय हैं।नीतू कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट में महिलाओं के लिए कुल 10,857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना के लिए 2,320 करोड़ रुपये, मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 250 महतारी सदन निर्माण, शहरी क्षेत्रों में 250 आंगनबाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 500 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है।उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के लिए 5 करोड़ रुपये और रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।नीतू कोठारी ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सुशासन, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और बुनियादी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 26 फरवरी को

बेमेतरा। कार्यालय कार्यपालन अभियंता/सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड-बेमेतरा द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (ष्ठङ्खस्रू) की बैठक आयोजित किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार मिशन की गठित समिति की बैठक 26 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत; कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग; मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी; जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास); जिला शिक्षा अधिकारी; उप संचालक जनसंपर्क; उप संचालक कृषि तथा उप वन मंडलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को पकड़ने में चौकी देवकर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बीते सोमवार को प्रार्थी जयपाल राजपुत उम्र 42 साल निवासी सिंघनपुरी थाना साजा जिला बेमेतरा ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रोहित कुमार पिता गोरेलाल निवासी करन चौराहा घोसिया थाना सरायअकील जिला कौशाम्बी (उत्तरप्रदेश) जो किराये के घर देवकर मे लेकर रहता था। आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग में आया हु अगर तुमको सरकारी नौकरी चाहिये तो लगा सकता हूं तब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, फोटो जिला सहकारी बैंक का पासबुक सबका फोटोकापी कराकर एवं पुलिस विभाग में वाहन चालक के नियुक्ति के लिए नगद 1,65,000/- रूपये रोहित को दिया उसके बाद उससे संपर्क किया तो भाग गया था उसके बाद खोजबीन किया पता नहीं चला मेरे मित्र भागचंद कुर्रे ग्राम मोहभटठा से उक्त बातो के बारे मे बताया तब भागचंद कुर्रे ने बताया, कि रोहित कुमार को पुलिस ड्रायवर के नौकरी के नाम पर भी 85,500/- रूपये, उसके बाद 12,000/- रूपये सुनील यादव निवासी देवकर से बाईक निलामी के संबंध में अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर पैसा लेकर छल किया है। बीते सोमवार को करीबन 02-03 बजे देवकर मे रोहित कुमार सिंह को देखा तो पैसा वापस करने बोला तो अभी मेरा पोस्टिंग होने वाला है कुछ दिन रूक जाओ पैसा वापस कर दूंगा बोलकर अपने थैला मे रखे अवार्ड शिल्ड को दिख रहा था, आईएएस अधिकारी बताकर मेरे और मेरे दोस्तो के साथ पैसा लेन देन कर छल किया है। कि रिपोर्ट पर चौकी देवकर थाना साजा में अपराध सदर धारा धारा 319 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई , जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद को चौकी स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी रोहित कुमार को हिरासत में लेकर पुछताछ कर उनके कब्जे से अवार्ड शिल्ड, मेडल को जप्त कर बरामद किया गया। आरोपी रोहित कुमार पिता गोरेलाल उम्र 33 वर्ष, निवासी करन चौराहा घोसिया थाना सरायअकील जिला कौशाम्बी (उत्तरप्रदेश) को गिरफ्तार कर विधि अनुसार कार्यवाही की गई। इस संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद, सउनि छोटे लाल बंजारे, प्रधान आरक्षक उमाशंकर ठाकुर, आरक्षक मोहित देवांगन, मनीष वर्मा, दीपक ठाकुर सहित चौकी देवकर के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ के बजट पूरी तरह से निराशाजनक है... देवांगन

सारंगढ़/ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने 2026-27 का बजट 24 फरवरी दिन मंगलवार को बजट पेश कुल 1,72 लाख करोड़ कृषि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 300 करोड़ ऐसी तरह किया है जो निराशाजनक है। सारंगढ बिलाईगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ताराचन्द देवांगन ने भाजपा सरकार के प्रदेश की बजट को निराशा व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह फीका निराशाजनक और दिशाहीन बताया है। यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है उद्योगपति हितैसी और जनता विरोधी है।किसानों और पिछडे जिलों की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेरने वाला है।

बेमेतरा से 8 युवा ने लिया आपदा मित्र का प्रशिक्षण

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आपदा से निपटने कि तैयारी के लिए भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में युवा आपदा मित्र तैयार किए जा रहे है। इसी के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5000 और रायपुर संभाग से 1250 आपदा मित्र तैयार किए जा रहा है। यह प्रशिक्षण, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना, माना कैंप, रायपुर में दिनांक 16 फरवरी से 22 फ़रवरी तक आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 101 यूवाओं ने युवा से, युवा आपदा मित्र बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया और इन्हे प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिसमे बेमेतरा से 8 युवा - लक्ष्मीन वर्मा, अंजू सिन्हा, कुसुम वर्मा, मनीष साहू, महेश चंद्राकर, शिवम रात्रे, राहुल जायसवाल, किशन वर्मा शामिल हुए। आपदा मित्र का प्रशिक्षण द्वारिका टंडन, छम्मन साहू, चंद्रहास साहू, कालेश्वर साहू द्वारा दिया गया। इन्होंने बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, सर्प दंश, आग लगना, ष्टक्क्रकैसे दे आदि विषयों को बहुत ही सहज एवं सरल तरीके से युवाओं को सिखाया। भविष्य में इन युवाओं क्क्रञ्ज किट प्रदान किया जाएगा और आवश्यकता पढ़ने पर देश की सेवा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

मोदी की गारंटी को दुगुनी रफ्तार देने का संकल्प है यह छत्तीसगढ़ बजट - नितेश सोनी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार बजट 2026 पेश होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला सोशल मीडिया सह प्रभारी नितेश सोनी ने इसका जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा छत्तीसगढ़_SANKALP_ बजट÷* प्रस्तुत किया गया । यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, पारदर्शी शासन और जनकल्याण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सुशासन, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और बुनियादी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यह बजट प्रदेश की समृद्धि और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा तय करेगा ।

डोगरीपाली झाल हुआ खुन से लतपत कुल्हाड़ी से 3 लोगों कि मौत

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ मूक पत्रिका

सारंगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले डोंगरीपाली के ग्राम झाल में मंगलवार को घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पड़ोस में रहने वाले भतीजे ने कथित वाद विवाद तना तनी के चलते अपने ही चाचा के परिवार के पांच सदस्यों पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं।जानकारी के अनुसार ग्राम झाल में एक ही परिवार के सदस्य अगल-बगल निवास करते हैं। रोजाना की तरह मंदो बाई सारथी (62) अपने परिवार के साथ घर में सो रही थीं। तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच उनके ही परिवार का भतीजा तुलसी सारथी टांगी लेकर घर में घुसा और नींद में सो रहे लोगों पर जानलेवा प्रहार शुरू कर दिया।हमले में मंदो बाई सारथी और उनके पुत्र राजेश सारथी (36) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन वर्षीय नाती प्रशांत सारथी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हमले की विभत्सता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला।घर के भीतर अचानक चीख-पुकार मच गई। जो भी बीच-बचाव के लिए सामने आया, आरोपित ने उस पर भी वार कर दिया। इस दौरान कुमार साय सारथी (65) और गर्भवती संजुक्ता सारथी (30) गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।जंगल जाने की बात कहकर निकला थापुलिस पूछताछ में सामने आया है कि तुलसी सारथी तड़के सुबह घर से यह कहकर निकला था कि वह टांगी लेकर जंगल लकड़ी लेने जा रहा है। कुछ ही मिनटों बाद पड़ोस से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जब परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक वह वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था।

पुराना विवाद बना वजह?- ग्रामीणों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच कुछ वर्ष पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि मामला समय के साथ शांत हो गया था, लेकिन सोमवार को फिर बहस हुई थी। पुलिस अभी हत्या के कारणों की हर पहलू से जांच कर रही है।

तीन दिन पहले ही लौटा था गांव-आरोपित के पिता शौकीलाल ने बताया कि तुलसी बाहर होटल में रोजी मजदूरी करता था और तीन दिन पहले ही गांव लौटा था। घटना के बाद वह भागने की कोशिश में था, लेकिन डोंगरीपाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

कृषि उन्नति योजना लाएगी समृद्धि, ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान:साहू

25 लाख किसानों को समृद्धि का तोहफा: दक्ष वैद्य

रायपुर/मूक पत्रिका

भाजपा किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी एवं हिन्द सेना युवा ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्ष वैद्य साहू ने 2026 बजट छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विकास का नया दौर लाएगा।उन्होंने कहा कि यह बजट पूर्णतः किसान हितैषी है और राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुँचाएगा। विशेष रूप से कृषि उन्नति योजना कृषक उन्नति योजना के तहत ?10,000 करोड़ का प्रावधान किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि उत्पादन को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दक्ष वैद्य साहू ने योजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह बजट न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य के रूप में नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।किसानों की आय बढ़ाने,उत्पादकता में वृद्धि और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए ?10,000 करोड़ का प्रावधान। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि पंपों के लिए ?5,500 करोड़ सूखे प्रभावित क्षेत्रों जैसे बस्तर, दुर्ग, रायपुर में फसल उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य। इससे लाखों एकड़ भूमि पर विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए ?300 करोड़,किसानों को बिना ब्याज के आसान ऋण उपलब्ध कराने से कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और वे नई फसलें धान, दलहन बो सकेंगे।मार्कफेड को ?6,000 करोड़, किसानों की उपज के भंडारण, खरीदी 437 लाख मीट्रिक टन धान और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इससे धान, गेहूँ और अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी खरीदी सुगम होगी। दक्ष वैद्य साहू ने कहा,यह बजट न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य के रूप में नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने युवा किसानों, महिला किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों से अपील की कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के नेतृत्व में इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वे किसानों को योजना के लाभ तक पहुँचाने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे।

पुनर्वास केंद्र में युवाओं से सीधा संवाद, मुख्य धारा में लौटने के साहस की सराहना

बीजापुर दौरे पर मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष: पुनर्वास केंद्र से स्कूल, अस्पताल और जेल तक व्यवस्थाओं की पड़ताल

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरधारी नायक ने अपने दो दिवसीय प्रवास की शुरुआत पुनर्वास केंद्र के दौरे से की। यहां उन्होंने मुख्यधारा में लौटे युवाओं से खुलकर बातचीत की। युवाओं ने नक्सल संगठन में बिताए समय की कठिनाइयों और वर्तमान में मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया। अध्यक्ष ने कहा कि समाज में लौटना बड़ा निर्णय है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से मजबूती से जोड़ा जाए।

बाल देखरेख संस्थान और कन्या शिक्षा परिसर का निरीक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर - अध्यक्ष ने बाल देखरेख संस्थान पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और उन्हें मिल रही शिक्षा व पोषण सुविधाओं की जानकारी ली। बच्चों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और पढ़-लिखकर आगे बढ़ने की इच्छा जताई। एजुकेशन सिटी स्थित कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं से पाठ पढ़वाकर उनकी समझ और आत्मविश्वास परखा गया। छात्राओं के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई।

समर्थ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण - दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास केंद्र में भोजन, आवास और प्रशिक्षण कक्षों का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष ने समावेशी और संवेदनशील वातावरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण - दौरे के दौरान जिला अस्पताल का भी जायजा लिया गया। ओपीडी, दवा वितरण, लैब और अन्य विभागों की व्यवस्था देखी गई। डॉक्टरों की उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर चर्चा हुई। पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों की देखभाल व्यवस्था का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता पर बल दिया गया।

उप जेल में बंदियों से बातचीत, शिक्षा और सुधार पर बल -उप जेल के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने बंदियों से सीधा संवाद किया। अधिकांश बंदी कम पढ़े-लिखे पाए गए।

उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन और अवसर से सुधार संभव है। जेल में भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।

कोतवाली थाना में कार्यप्रणाली की समीक्षा, संवेदनशील पुलिसिंग के निर्देश -कोतवाली थाना में शिकायत निवारण व्यवस्था और दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।दौरे के दौरान कलेक्टर संबित मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव,एसडीएम जागेश्वर कौशल,सहायक आयुक्त देवेंद्र सिंह,सीएमएचओ बी आर पुजारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गौधाम संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित, 5 मार्च तक आवेदन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बेमेतरा द्वारा गौधाम संचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (श्वह्रढ्ढ) आमंत्रित की गई है। जारी सूचना के अनुसार श्वह्रढ्ढ जारी करने की तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।निर्धारित प्रपत्र-7 में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2026, दोपहर 3:00 बजे तक रखी गई है। इच्छुक संस्थाएं अपना आवेदन कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में जमा कर सकती हैं। जारी सूचना में बताया गया है कि गौधाम में निराश्रित एवं घुमंतु गौवंशीय पशुओं तथा गृह विभाग द्वारा कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 (संशोधित 2011) एवं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परीक्षण नियम 2014 के अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं को ही विस्थापित किया जाएगा।जिला बेमेतरा अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों पर स्थित गोठानों में गौधाम की स्थापना की जानी है। इसके लिए भूमि, संचालन की शर्तें, क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, पात्रता, कार्यकाल, चयनित संस्था की जिम्मेदारियां, मानव संसाधन व्यवस्था, योजना के वित्त पोषण एवं शासन की अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरण कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला बेमेतरा में उपलब्ध रहेगा। इच्छुक एवं पात्र संस्थाओं से समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे पुल निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, मौके से विभागीय इंजीनियर रहते हैं नदारद

पुल निर्माण कार्य अकुशल मजदूरों के भरोसे

सक्ती/जैजैपुर/मूक पत्रिका

पुल निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी एक गंभीर समस्या है, जो घटिया सामग्री, कमजोर नींव, तकनीकी खामियों और भ्रष्टाचार के कारण होती है।

यह अक्सर समय से पहले पुल टूटने और बड़े हादसों का कारण बनती है, जिससे जन-धन की हानि होती है। इसके प्रमुख कारणों में ठेकेदारों की लापरवाही, खराब निरीक्षण और अवैध उपठेका शामिल रहता है। ऐसा ही एक मामला सक्ति जिले के दो विकासखंड मालखरौदा अंतर्गत नवागांव एवं जैजैपुर अंतर्गत सलनी के आश्रित ग्राम धनुहार पारा के मध्य बोराई नदी में बन रहे पुल निर्माण की है जहाँ ठेकेदार द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर पुल की निर्माण कार्य कर रहा है।जिसकी लागत राशि 4.75 करोड़ रुपये है जिसकी कार्यावधि भी समाप्त हो चुकी है और उच्चस्तरीय पुल अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है। यह पुल निर्माण की कार्यादेश दिनांक 29/09/2023 से 28 /10/2024 लगभग एक वर्ष में बन जाना चाहिये था लेकिन दो वर्ष से अधिक समय हो गया है और निर्माण कार्य अधूरा है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार एवं विभागीय इंजीनियर एवं अधिकारी इस उच्चस्तरीय पुल निर्माण को लेकर कितने गम्भीर हैं। पुल निर्माण में जंक लगे सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं कन्क्रिटिंग में मिट्टी युक्त रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है और कन्क्रिटिंग में सही ढंग से तराई भी नही किया जा रहा है इसके अलावा कंक्रीट कार्य में फिनिशिंग भी नही है जिस प्लास्टर कर के छिपा दिया जा रहा है।

मौके से नदारद रहते हैं इंजीनियर

कार्य स्थल पर रोजाना कन्क्रिटिंग का कार्य चल रहा है और मौके पर ठेकेदार का इंजीनियर रहता है और न तो विभागीय इंजीनियर मौके पे रहता है पुल का सारा निर्माण कार्य अकुशल मजदूरों के भरोसे चल रहा है। और कंक्रीट कितना बजबूत होगा इसके लिए क्यूब में कंक्रीट को भरा जाता है उसके बाद उसको लैब में उसकी मजबूती का टेस्ट किया जाता है लेकिन मौके पर मजबूती टेस्ट के लिए कोई क्यूब नही भरा जा रहा है ऐसे में सारा काम भगवान भरोसे ही चल रहा है और ठेकेदार एवं विभागीय इंजीनियर भविष्य में इस पुल से आवागमन करने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं कहेंगे तो गलत नही होगा। एक तरफ बीजेपी डबल इंजन की सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा लेकिन उसी अधीनस्थ प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खुलेआम भ्रष्टचार को अंजाम दिया जा रहा है और बीजेपी सरकार तमाशबीन बनी बैठी है। इसी को कहते हैं मुख में राम बगल में छुरा।।

खैरगुड़ा प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शानदार शुभारंभ

बस्तर/मूक पत्रिका

बस्तर विकास खंड के मधोता 02 खैरगुड़ा में आयोजित खैरगुड़ा प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप ने किया। उन्होंने टॉस कराकर प्रतियोगिता का आगाज किया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया। शंकुतला कश्यप ने कहा, ÷खेल भावना से खेलें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। ग्राम पंचायत में ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए, ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले।÷ उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर है। मैच का शुभारंभ करने के पूर्व ग्राम पुजारी के द्वारा ग्राम ईष्ट देवी व माटी माता का पूजन कर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहला मुकाबला बालेंगा विरूद्ध टेमरा के बीच खेला गया, जिसमें बालेंगा टीम ने शानदार जीत हासिल की।इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप, विशिष्ट अतिथि ग्राम पुजारी गंगाधर ठाकुर, तयसिंह ठाकुर, सोमनाथ, सोनसाय, समलू, त्रिनाथ ठाकुर, पतिराम,बीजुराम ,रूपसिंह,मुरली,बोगलु सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे।

प्रतियोगिता आयोजन समितिः संजय सिंह ठाकुर, नरेश ठाकुर, मनोज कुमार, हरगोविंद सिंह, मोहित ठाकुर, उदय, पुरन, डोमेश सिंह, हलधर, नीलम, लोकेश अजीत, किशन, अपाल, वैभव सिंह ठाकुर,हेमराज, खेमेश्वर ठाकुर,केशव,खिरेन्द्र,लखन, विजय कश्यप।प्रतियोगिता के आयोजन में समिति के सदस्यों ने कड़ी मेहनत की है, ताकि युवाओं को एक अच्छा मंच मिल सके। प्रतियोगिता के दौरान दर्शकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज शाखा बेमेतरा ने राजस्व लक्ष्य किया शत-प्रतिशत पूर्ण

अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही, लाखों रुपये अर्थदण्ड वसूल

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बेमेतरा को वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा गत वर्ष की तुलना में दुगुना राजस्व लक्ष्य निर्धारित करते हुए 450.00 लाख रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया था। उल्लेखनीय है कि खनिज विभाग द्वारा सतत निगरानी, प्रभावी राजस्व संग्रहण एवं सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से 24 फरवरी 2026 तक ही 450.00 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित कर ली गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आगामी माह मार्च 2026 में भी खनिज राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है, जिससे जिले को निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन की सक्रिय कार्यप्रणाली, नियमित निरीक्षण, पारदर्शी खनिज प्रबंधन प्रणाली एवं राजस्व वसूली की सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है।अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी कार्यवाही

जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। माह जनवरी एवं फरवरी 2026 के दौरान खनन क्षेत्रों एवं परिवहन मार्गों पर सघन जांच एवं संयुक्त दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए।अवैध परिवहन के 16 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें कुल ?2,57,000/- की अर्थदण्ड राशि वसूल की गई।अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण में कुल ?1,23,500/- की अर्थदण्ड राशि अधिरोपित कर वसूल की गई। यह समस्त कार्यवाही माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के प्रावधानों के तहत की गई।

सतत निगरानी एवं राजस्व संवर्धन पर विशेष जोर–खनिज शाखा द्वारा जिले में संचालित खदानों की नियमित समीक्षा, ई-रॉयल्टी सत्यापन, परिवहन चालानों की जांच तथा राजस्व की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संपदा के संरक्षण एवं शासन को अधिकतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं पारदर्शी राजस्व प्रणाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

कोंटा में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अहम बैठक

कोंटा/मूक पत्रिका

दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कोंटा में संचालित आश्रम, पोटाकेबिन एवं अन्य आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक और व्यवस्थागत गुणवत्ता की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनपद अध्यक्ष कुसुमलता कवासी एवं जनपद उपाध्यक्ष व कोंटा ब्लॉक शिक्षा समिति के अध्यक्ष माड़वी हिड़मा की पहल पर कोंटा आईटीआई कॉलेज के सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। इसमें श्रीनिवास राव (बीईओ कोंटा), मंडल संयोजक पी श्रीनिवास सहित आश्रम व पोटाकेबिन विद्यालयों के अधीक्षक, सीआरसी समन्वयक और शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक में विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, भोजन व्यवस्था, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधीक्षकों को नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध पाठ्यक्रम पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनपद अध्यक्ष कुसुमलता कवासी ने कहा कि आश्रम व पोटाकेबिन विद्यालय आदिवासी बच्चों के भविष्य की आधारशिला हैं, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं माड़वी हिड़मा ने कहा कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएं और हर माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए।

आर्थिक सर्वेक्षण पर विपक्ष का सवाल, कहा– 'कपोल-कल्पित आंकड़ों से नहीं छिपेगी सच्चाई'

बेमेतरा/मूक पत्रिका

राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते और यह मात्र ÷कपोल-कल्पित संभावनाओं÷ पर आधारित दस्तावेज है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार द्वारा बताई जा रही प्रति व्यक्ति आय जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। उनका कहना है कि प्रदेश की आम जनता आज भी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के दावों को विपक्ष ने ÷हवा-हवाई÷ बताया है। नेताओं ने कहा कि सरकार आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि मात्र दो वर्षों में ही भाजपा सरकार विकास और रोजगार के मुद्दों पर पूरी तरह असफल साबित हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

लोकतंत्र प्रहरी संघ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज कुमार को, वरिष्ठ पदाधिकारियों का जताया आभार..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले में लोकतंत्र प्रहरी संघ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मनोज कुमार मेहर को जिला अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मनोज कुमार मेहर ने कहा कि यह दायित्व उनके लिए केवल पद नहीं, बल्कि संगठन के विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने माना कि यह अवसर उन्हें मार्गदर्शकों के सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिला है।मनोज कुमार मेहर ने कहा कि यह दायित्व उनके लिए केवल पद नहीं, बल्कि संगठन के विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने माना कि यह अवसर उन्हें मार्गदर्शकों के सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिला है।नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वे संगठन और जिले की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनका कहना है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मनोज कुमार ने भविष्य में भी सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा जताई है। उन्होंने दोहराया कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। जिले में इस नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और संगठन को इससे नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरिया को बड़ी सौगात : बजट में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा, अटल चौक में आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न..

सारंगढ़-बिलाईगढ/ मूक पत्रिका

बजट 2025-26 में सरिया क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ शासन ने सरिया में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। इस फैसले को क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रायगढ़ विधायक एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा बजट में यह प्रावधान किए जाने के बाद सरिया और आसपास के ग्रामीण अंचल में उत्साह का माहौल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को नई दिशा–नर्सिंग कॉलेज खुलने से सरिया ही नहीं, पूरे आसपास के गांवों के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर बेटियों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ तैयार होने से क्षेत्र के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती मिलेगी।

विकास की मजबूत नींव–क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह निर्णय सरिया के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। शिक्षा विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसे सरिया के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

अटल चौक में आतिशबाजी, मिठाई बांटकर खुशी–घोषणा के बाद सरिया के अटल चौक में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुरारी नायक, भाजपा मंडल सरिया अध्यक्ष प्रदीप सतपथी, महामंत्री महेश बारीक, कैलाश नायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस फैसले के लिए आभार जताया।

उम्मीदों को पंख–नर्सिंग कॉलेज की घोषणा से सरिया अब शिक्षा और स्वास्थ्य के नए केंद्र के रूप में उभरने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह संस्थान न सिर्फ युवाओं के सपनों को दिशा देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की रफ्तार भी तेज करेगा।

सिंचाई व पेयजल से किसानो को मिलेगी बड़ी राहत

बेमेतरा विधानसभा के किसानों को मिली बड़ी सौगात

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 'संकल्प' थीम पर आधारित इस बजट में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, सिंचाई विस्तार, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था, सड़क एवं सुरक्षा ढांचे,स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है।बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को इस बजट में बहुआयामी विकास की सौगात मिली है। जिसमे शिवनाथ नदी के अमोरा घाट पर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमोरा बैराज निर्माण को स्वीकृति दी गई है। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि अमोरा बैराज की स्वीकृति बेमेतरा के किसानों के वर्षों पुराने सपनों को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है इससे न केवल सिंचाई की स्थाई व्यवस्था होगी बल्कि फसल उत्पादन में वृद्धि आएगी और उत्पादन मे बढ़ोतरी और पेयजल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी द्य साथ ही अमोरा बैराज के बनने से क्षेत्रवासियों को शुद्ध एवं मीठा पेयजल उपलब्ध होगा। यह परियोजना क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी द्य

6 विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए मिली प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बेमेतरा आगमन के दौरान घोषित 6 नवीन विद्युत सब-स्टेशन को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सब-स्टेशनों के निर्माण से किसानों को कृषि पंपों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति मिलेगी, लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या दूर होगी तथा ग्रामीण-शहरी उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा द्य

देवरबीजा कॉलेज में भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

बजट में देवरबीजा कॉलेज के लिए भवन

निर्माण की स्वीकृति भी मिली है इस दौरान विधायक दीपेश साहू ने कहा कि महाविद्यालय भवन केवल एक भवन निर्माण नहीं बल्कि हमारे बेटों बेटियों के उज्जवल भविष्य की नीव है नए भवन से छात्र-छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा द्य आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अपने ही क्षेत्र में प्राप्त होगी द्य छात्र-छात्राओं को दूर-दराज शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी जिस समय और आर्थिक व दोनों की बचत होगी साथ ही अभिभावक में भी सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी द्य

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में पुल पुलिया एवं सड़क निर्माण से आवागमन होता सुदृढ़

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गावों मे सड़कों एवं पुल-पुलिया निर्माण के स्वीकृति मिली है विधायक दीपेश साहू ने कहा कि पुल पुलिया निर्माण की स्वीकृति के लिए कहा की हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और बहू प्रतिक्षित सौगात है बरसात के दिनों में जिन मार्गो पर आवागमन बाधित हो जाता था अब वहां सुगम और सुरक्षित आवागमन संभव होगा इससे ग्रामीण किसानों विद्यार्थियों और मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा तथा आपातकालीन सेवा भी समय पर पहुंच सकेगी यह निर्माण केवल एक सुविधा नहीं बल्कि गांव और शहर के बीच मजबूत संपर्क है व्यापार में वृद्धि समग्र विकास की नई राह खोलेगा यह कदम क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला है और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

बेमेतरा में साइबर थाना थाना की स्थापना के लिए मिली स्वीकृति

विधायक साहू ने कहा कि साइबर थाना खुलना समय की सबसे बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी हैकिंग और साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में स्थानीय स्तर परत्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी द्य पीड़ित को शिकायत दर्ज करने और समाधान पाने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा या कम आम नागरिकों की सुरक्षा जागरूकता और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा ।

बेमेतरा व बेरला क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्कूल भवन निर्माण की बड़ी सौगात

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेमेतरा एवं बेरला क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नवीन स्कुल भवन निर्माण को भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा तथा बच्चों को अपने ही गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा–प्रदेश सरकार द्वारा बेमेतरा और बेरला क्षेत्र के गांवों में नए स्कूल भवनो की स्वीकृति मिलना शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे ग्रामीण बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो, ताकि आने वाली पीढ़ी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। यह बजट सच मायनों में गांव, गरीब, किसान और विद्यार्थियों के विकास को समर्पित है।÷विधायक दीपेश साहू ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव सांय एवं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट किसान, युवा, छात्र और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और बेमेतरा के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

संपादकीय

मोतियाबिंद शिविर बना त्रासदी ?

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद संक्रमण से नौ मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और नौ अन्य की एक आंख की रोशनी चली गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस शिविर का आयोजन एक स्थानीय निजी अस्पताल की ओर से किया गया था और यहां कई लोगों ने 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत आंख के आपरेशन कराए। प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद स्थानीय प्रशासन ने माना कि इन मामलों में गंभीर चूक हुई है।सामान्यत- चिकित्सक मरीज के मर्ज को ठीक कर उसके जीवन को बेहतर बनाता है, इसलिए उसे ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। ऐसे में किसी चिकित्सक या उनके सहायक की इस तरह की लापरवाही को किस तरह देखा जाएगा। यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अमले में कर्तव्य के प्रति कोताही और असंवेदनशीलता की जड़ें किस तरह गहरी होती जा रही हैं।यह घटना कोई पहला मामला नहीं है। मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद संक्रमण से आंखों की रोशनी खत्म हो जाने के मामले देश भर में अक्सर सामने आते रहते हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हों या निजी, इस तरह की लापरवाही अब आम बात हो गई है। गोरखपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब तीस मरीजों की आंख का आपरेशन किया गया था, जिसके बाद चौबीस घंटे के भीतर अठारह मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?हालांकि ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन साफ है कि उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के जख्मों पर मामूली मुआवजे का मरहम लगाकर मामले को निपटा दिया जाता है, जिस कारण व्यवस्था में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आलम जस का तस बना रहता है। जाहिर है, जब तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।खूबसूरत दुनिया की सुंदरता देखने के लिए आंखों की रोशनी बहुत ही अनमोल है, जिसे बुढ़ापे तक सुरक्षित रखना जरूरी है। हमारे शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी अगर शरीर के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग की बात करें, तो वह आंखें होती हैं। हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम होने के साथ-साथ गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है। इसमें मोतियाबिंद बहुत आस समस्या है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रूवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार

(ललित गर्ग)

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

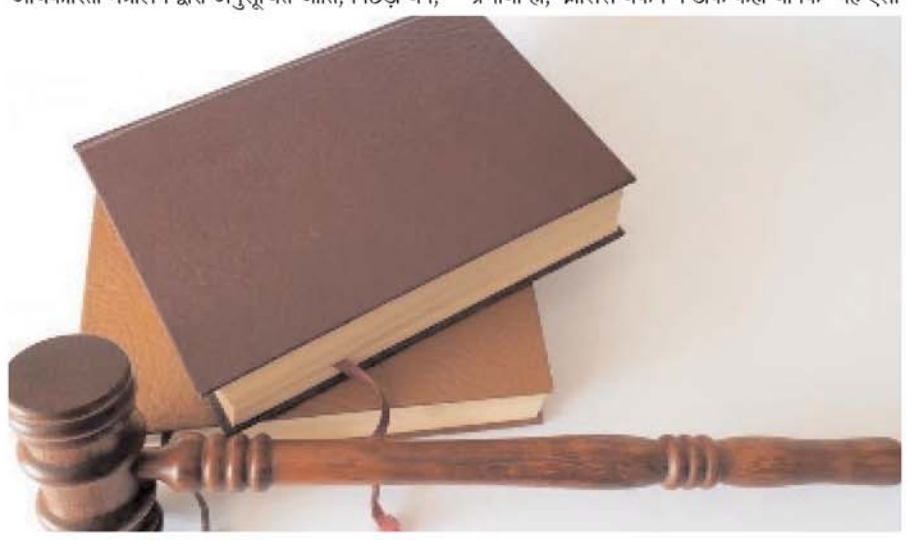

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग,

दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके। 2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।लेखक, पत्रकार, स्तंभकार। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

क्या है पैक्स सिलिका ? इसमें शामिल होकर भारत ने कैसे चीन को बेचैन कर दिया है?

(नीरज कुमार दुबे)

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी।

भारत ने आज अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ते हुए एक अहम रणनीतिक कदम उठाया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दोनों देशों ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भरोसेमंद और लचीला सहयोग तंत्र विकसित करना है। हम आपको बता दें कि पैक्स सिलिका अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख ढांचा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क बनाना है। घोषणा पत्र में आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दीर्घकालिक वैश्विक समृद्धि का परिवर्तनकारी साधन बताया गया है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। वैष्णव ने बताया कि भारतीय इंजीनियर उन्नत दो नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग दस लाख अतिरिक्त कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी और भारत इस प्रतिभा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बन सकता है। छात्रों को विश्वस्तरीय चिप डिजाइन उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात भी उन्होंने कही।

इस अवसर पर बोलते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर मार्ग चुनने की इच्छा इस साझेदारी को विशिष्ट बनाती है। व्यापार समझौते से लेकर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तक दोनों देशों के बीच असीम संभावनाएं हैं।

अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने इसे भू राजनीतिक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि यह पहल हथियारबंद निर्भरता और दबाव आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्वीकार करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह देखा जाना चाहिए। साथ ही, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह साझेदारी भारत को आर्थिक और तकनीकी आधार प्रदान करेगी, जिससे वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सके। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की अमेरिकी सोच भारत के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में डिजिटल अवसंरचना और डेटा केंद्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पारंपरिक सैन्य साधन। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण अत्यधिक पूंजी और तकनीकी परिशुद्धता मांगता है। यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य पाना है तो उसे नीतिगत स्थिरता, अनुसंधान निवेश और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी एक ध्रुव पर अत्यधिक निर्भर न हो। बहरहाल, पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी एक अवसर है, जिससे वह 21वीं सदी की तकनीकी व्यवस्था में सक्रिय निर्माता की भूमिका निभा सकता है। यह कदम भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि मानक निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में है। यदि इस पहल को दीर्घकालिक रणनीति और घरेलू सुधारों के साथ जोड़ा गया, तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति कहीं अधिक सुदृढ़ हो सकती है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

देशों की आर्थिक दशा बदलती एआई

नई दिल्ली में चल रहा 'एआई इम्पैक्ट समिट' अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था पर एआई के बढ़ते प्रभाव पर हुई चर्चाएं अहम हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब इस नई तकनीक से प्रभावित होने लगी हैं। यह कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि एआई एक क्रांतिकारी तकनीक है। इससे पहले जो भी तकनीकी बदलाव हुए हैं, उन्होंने कमोबेश शारीरिक श्रम पर असर डाला था। उनसे हमारे भौतिक कामकाज प्रभावित हुए थे, पर एआई कुशल कामगारों को प्रभावित कर रही है। एआई समिट में यह भी चर्चा हुई कि इससे लोगों की उत्पादकता कितनी बढ़ रही है और उनके काम करने के तरीके कितने बदल रहे हैं।

(अरुण कुमार)

यह बदलाव काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि एआई में निवेश काफी ज्यादा हो रहा है। मसलन, पिछले साल जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के बुनियादी ढांचे को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए लगभग 500 अरब डॉलर तक के निवेश की घोषणा की। वहां 'मेटा' जैसी बड़ी कंपनियां भी अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। चीन भी इस तरह के कामों में पीछे नहीं है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो देश एआई में सर्वोच्चता हासिल कर लेगा, वह विश्व-व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बना लेगा।

यही वजह है कि एआई को 'पब्लिक गुड्स' के रूप में विकसित करने की वकालत की जाती है, ताकि यह सबको सुलभ हो और सभी इसका इस्तेमाल कर सकें। यह मांग इसलिए भी हो रही है, क्योंकि एआई से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। यह किसी उद्योग के लिए जरूरी शोध कर सकती है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तत्काल बता सकती है कि कहां उसके लिए बेहतर कच्चा माल उपलब्ध है और कहां से उसे लाना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। इसी तरह, मार्केटिंग की रिपोर्ट तैयार करने में भी एआई से काफी मदद मिलती है। कहां और किस क्षेत्र में कैसी मांग है, इससे यह पता करना आसान हो जाता है। यानी, सूचनाएं उपलब्ध रहने से तमाम उद्यमों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। इस तरह उनकी उत्पादन लागत कम हो सकती है।

इसी तरह, नए-नए शोध में एआई से फायदा मिल सकता है। मिसाल के लिए, अब प्रोटीन की संरचना समझने के लिए 'अल्फाफोल्ड' सॉफ्टवेयर की मदद ली जाने लगी है। यह प्रोटीन की थ्रीडी संरचना बना देती है, वह भी थोक के भाव से। पहले प्रोटीन की एक संरचना के विश्लेषण के लिए एक शोध-कार्य होते थे, लेकिन 'अल्फाफोल्ड' हजार शोध के बराबर काम करने में सक्षम है। इससे दवाओं के निर्माण में फायदा होता है। इस जैसे तमाम पेशेवर कामों में अब एआई की भागीदारी संभव होगी। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम किसी डॉक्टर या सीए के इंटर्न के रूप में किसी एआई मॉडल को सेवा देते देखें।

एआई भाषायी बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को मदद कर सकती है। अभी सुदूर देशों के साथ संपर्क साधना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उद्यमी भाषायी तौर पर कुशल नहीं होते, लेकिन एआई द्वारा आसानी से मूल भाषा में अनुवाद करके सामग्री उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिल सकती है। इससे नई-नई चीजों के ईजाद में काफी सहायता मिलेगी और कामकाज में तेजी आ सकेगी।

जीवन-स्तर की गुणवत्ता में एआई द्वारा सुधार लाना आर्थिक नजरिये से सुखद माना जाता है। एआई पेशेवर लोगों की क्षमता बढ़ाने में मददगार होगी। इससे उनके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सूचनाएं न सिर्फ काफी तेजी से आ सकेंगी, बल्कि उनका गहन विश्लेषण भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इससे कर्मियों की क्षमताओं में इजाफा होगा। वित्तीय बाजार पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और वित्तीय योजनाएं बनाने में एआई पेशेवरों की मदद कर सकेगी।

हालांकि, इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस पर हमें कहीं अधिक संजीदगी से काम करना होगा। जैसे, सन माइक्रोसिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला ने एआई समिट में बताया कि एआई की वजह से पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं और 2030 तक कॉल सेंटर व बीपीओ जैसे कामों में लोगों की जरूरतें खत्म हो सकती हैं। जाहिर है, अब काम करने के तरीके बदल रहे हैं और उसी बदलाव के अनुसार हमें लोगों की जरूरतें भी पूरी करनी होंगी। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत में महत्वाकांक्षी नौजवानों की संख्या दुनिया

में सबसे अधिक है।

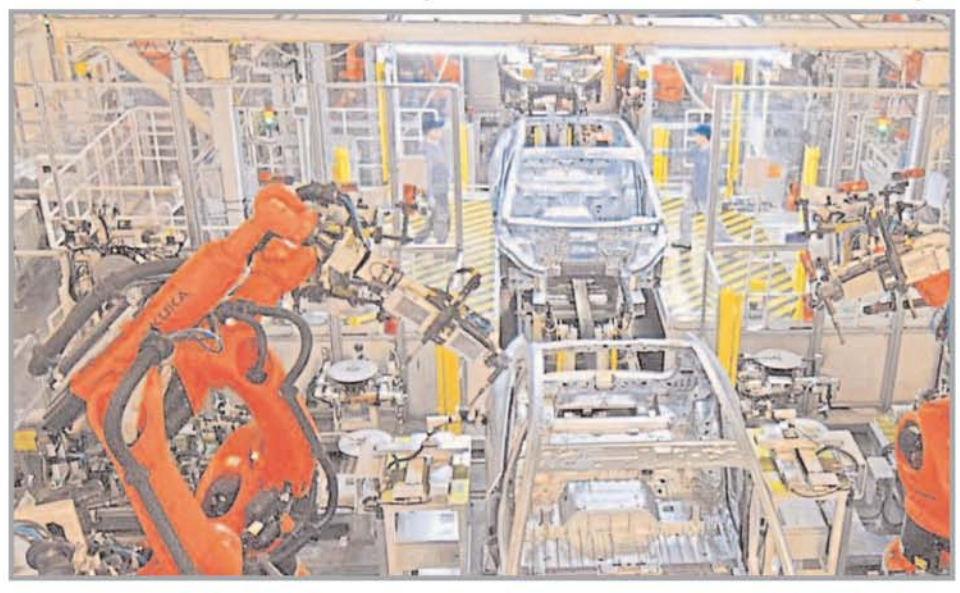

एआई से कुछ क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन भी होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में शुरुआती दौर में मांग घट सकती है, जिसके लिए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा और कौशल जिनके पास होगा, वे आगे बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि एआई में अमेरिका और चीन की तेजी को बाकी दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे देशों के बीच ठीक उसी तरह असमानता बढ़ सकती है, जिस तरह समाज में कुशल और अकुशल लोगों के बीच गैर-बराबरी है। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि एआई-सक्षम देश नव-साम्राज्यवादी ताकत बन सकती हैं और वे उन मुल्कों पर दबाव बना सकती हैं, जो एआई अपनाने में कमजोर रहेंगी। इससे दुनिया में आर्थिक विषमता का एक नया चक्र शुरू हो सकता है।

अच्छी बात है कि एआई से अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए भारत जैसे देश लगातार काम कर रहे हैं। हमें कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला है, शोध कार्यों के लिए माहौल सुधारना। इसके लिए उच्च शिक्षण व शोध संस्थानों को पहल करनी चाहिए और शोध-संबंधी माहौल की जो कमियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। सरकारों को भी शोध व विकास पर अपने खर्च बढ़ाने होंगे। दूसरा काम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। बेशक, नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी नई-नई तकनीक को समझ सकें, लेकिन कक्षा के मुताबिक उनकी मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। 'कैसे हमें सीखना चाहिए' यह सीख हमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बच्चों को सिखानी होगी। अच्छा होगा, भारत यह पहल करे कि 'ग्लोबल साउथ' के देश आपस में मिलकर एआई पर काम करेंल्र। इससे एआई का हर मोर्चे पर अधिकतम फायदा उठाया जा सकेगा। (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री है)।(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली

आधार आधारित उपस्थिति, एएनसी पंजीयन व संस्थागत प्रसव पर विशेष जोर

स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग को दिए समन्वित कार्य के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने मंगलवार को महिला बाल विकास एवं जिला स्वास्थ्य समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की। यह बैठक स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में आधार बेस्ड अटेंडेंस, गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन, समय पर पूर्ण जांच, संस्थागत प्रसव, मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, टीकाकरण, एनसीडी (नॉन -कम्युनिकेबल डिजीसेस), एचआईवी जांच सहित अन्य प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए।उन्होंने संस्थागत प्रसव की दर बढ़ाने तथा गर्भवती महिलाओं की प्रारंभिक एवं पूर्ण पंजीयन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चिन्हांकित हितग्राहियों का रिकॉर्ड मिलान करें, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों की जानकारी का एकीकृत सत्यापन कर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या लक्ष्य पूर्ति में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) को विकासखंडवार सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने तथा दवाइयों की उपलब्धता एवं पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण पुनर्वास, सुपोषण अभियान, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग, टीकाकरण सत्रों की नियमितता तथा आंगनबाड़ी-स्वास्थ्य अमले के संयुक्त फील्ड विजिट जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग का समन्वित प्रयास ही मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक होगा। कलेक्टर ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करते हुए जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर, सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे, जिला अस्पताल प्रबंधन डॉ. स्वाति यदु, सभी बीएमओ, जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित स्टाफ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय सरकार का बजट सुशासन से समृद्धि का प्रतीक : रत्नावली कौशल

8200 करोड़ का महतारी वंदन तोहफा मातृशक्ति सशक्त, बेटियों को 1.5 लाख का उपहार

रायपुर/मूक पत्रिका

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने 1.72 लाख करोड़ रुपये के 'संकल्प' बजट 2026 का भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह बजट समावेशी विकास का प्रतीक है। रत्नावली कौशल ने कहा यह बजट न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। 'सुशासन से समृद्धि' का यह संकल्प छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के लिए वरदान सिद्ध होगा।बजट की प्रमुख घोषणाएँ महतारी वंदन योजना ?8200 करोड़,70 लाख से अधिक विवाहित, विधवा,परित्यक्त एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्रतिमाह ?1000 की आर्थिक सहायता।

यह योजना घरेलू खर्च,बच्चों की शिक्षा-पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगी। अब तक 14,000 करोड़+ वितरित।कृषि उन्नति योजना ?10,000 करोड़,25 लाख किसानों विशेषकर छोटे-सीमांत को लाभ। सिंचाई सुविधाएँ मजबूत कर आय दोगुनी करने का लक्ष्य। ?5500 करोड़ कृषि पंपों हेतु। रत्नावली कौशल ने कहा कि रानी दुर्गावती योजना बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने पर ?1.5 लाख–कन्या भ्रूण हत्या रोकने, शिक्षा-विवाह हेतु क्रांतिकारी प्रावधान। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विकास बस्तर एजुकेशन सिटी ?100 करोड़–पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा क्रांति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ?2000 करोड़–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ सशक्त।शिक्षा 5 नालंदा लाइब्रेरी हेतु ?22 करोड़–ज्ञान केंद्र स्थापना। रत्नावली कौशल के उद्धरण ÷महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। रानी दुर्गावती योजना हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करेगी। बस्तर जैसे क्षेत्रों के लिए शिक्षा-स्वास्थ्य प्रावधान सराहनीय हैं। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विभा अवस्थी के नेतृत्व में इन योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन हेतु कटिबद्ध है। रत्नावली कौशल ने प्रदेश की सभी महिलाओं से अपील की इन क्रांतिकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ, हमारा छत्तीसगढ़ समृद्धिशाली बने।÷

विभागीय योजनाओं के अपेक्षित प्रगति में कमी पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार : कलेक्टर

समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों, विभागीय योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारियों की समय सीमा ली। बैठक में प्रशासनिक कसावट लाने को लेकर एक अहम संकेत देखने को मिला। कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं की अपेक्षित प्रगति निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपेक्षित प्रगति में कमी लक्ष्य का सीधा असर आम जनता तक पहुँचने वाले लाभों पर पड़ता है। उन्होंने इस स्थिति अधिकारियों को जवाबदेही के साथ दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाने निर्देशित की।समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने मुख्य पाया कि कई महत्वपूर्ण विभागों में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर है। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रकरणों के निराकरण और विभागीय लक्ष्य की पूर्ति में समय-सीमा का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए।

आवंटित राशि का असर धरातल पर दिखे-कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है बजट का सही उपयोग होना चाहिए। आवंटित राशि का धरातल पर असर दिखनी चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को चेतावनी देते गाइडलाइन्स का पालन जवाबदारी पूर्वक करने कहा।

प्रदर्शन में सुधार करने के निर्देश-कलेक्टर ने लक्ष्य आधारित कार्ययोजना को तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने कहा। सभी अधिकारियों को एक कार्ययोजना निर्धारित करने कहा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे पिछड़े हुए लक्ष्यों की भरपाई कैसे करेंगे।कलेक्टर ने ''फील्ड विजिट'' में बढ़ोतरी करने भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल ऑफिस तक सीमित ना रहें, फील्ड विजिट कर योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करें। उन्हें सप्ताह में अनिवार्य रूप से फील्ड में जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन करना कहा।

प्रदर्शन के आधार पर होगी कार्रवाई-कलेक्टर ने कहा कि प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ''यदि आगामी समीक्षा बैठक तक प्रगति में सुधार नहीं दिखा, तो संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने, वेतन वृद्धि रोकने जैसी कार्यवाही की जाएगी। प्रतिकूल प्रविष्टि देने की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभागवार समीक्षा में कमियों को दूर करने के निर्देश-कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कमियों को दूर कर सारगर्भित रूप से निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने कहा।

कलेक्टर ने लोक निर्माण को अधूरी सड़कों व स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र टेंडर कर मानसून से पहले पूर्ण करने कहा। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड वितरण और टीकाकरण के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करने निर्देशित की।

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन संपन्न

रायपुर/मूक पत्रिका

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक दिवसीय राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन ÷भारत मंडपम÷ नई दिल्ली में बीते मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ . उक्त सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह सहित देश के सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।सम्मेलन मुख्य रूप से राज्यों में स्थानीय निकाय के निर्वाचन कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। सम्मेलन में अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्थानीय चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की विधान सभा की निर्वाचक नामावली का डाटा शीघ्रातिशीघ्र एवं यथासंभव 7 दिवस के भीतर प्राप्त होना चाहिए ताकि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय एवं पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली निर्धारित समय में तैयार कराकर चुनाव संपन्न करा सके . उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसाधनों के सदुपयोग की दृष्टि से राज्यों की आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम) उपलब्ध कराया जाना चाहिए . अजय सिंह ने यह भी बताया कि जनवरी -फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के नागरीय एवं पंचायतों के लिए चुनाव एक साथ 36 दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न कराये गए।भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्यों के निर्वाचन आयोगों द्वारा उठाये गए सभी बिंदुओं पर विचार उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु भी आश्वस्त किया गया .सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवन्त कुमार राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं आई टी विशेषज्ञ डॉ सत्यकाम बेहार उपस्थित रहे।

प्रथम चरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण 27-28 फरवरी को, 19 मार्च को रिफ्रेशर प्रशिक्षण

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपादित किया जाना है। इसके प्रथम चरण अंतर्गत मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में 01 मई से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में कार्यों के सफल संपादन हेतु राज्य शासन के अधिकारियों का विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इसी क्रम में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण 27 एवं 28 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय के दृष्टि सभाकक्ष, बेमेतरा में प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण में जनगणना निदेशालय, छत्तीसगढ़ से सुश्री रश्मिता स्वाइन एवं शिवम दास प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन देंगे। इसके अतिरिक्त एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण 19 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनगणना मनोज कुमार महिलागे एवं बलवंत सोमकुंवर प्रशिक्षक के रूप में सहभागिता करेंगे। जनगणना 2027 के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हैं। जिला स्तर पर समस्त प्रशिक्षणों के लिए जिला जनगणना अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वे इस प्रशिक्षण सहित आगामी सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय एवं सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षण में निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर जनगणना कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

सरसीवा थाना मे कार्यवाही नही होने पर पीड़ित पक्ष ने कि पुलिस अधीक्षक से न्याय कि गुहार

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

सरसीवा थाना अंतर्गत आने वाले टाटा निवासी रोहित कुमार साहू एवं चालक धानेश्वर साहू, अपने हाइवा मे 20/02/2026 समय लगभग रात्रि 12 से 12:30 बजे ढोटमा रेत खदान (रियलिटी) से रेत भरकर वापस आ रहे थे। तभी सरसीवां पेंड्रावन चौक पर नारायण साहू पिता घनश्याम साहू, उमा साहू पिता खगेश साहू , सामू केशरवानी, मनोज कुर्रे , गोलू साहू, एवं अन्य 12 से 13 लोगों उनका वाहन को सामने आकर रोका । गाड़ी रोककर देखने पर नारायण साहू एवं उमाशंकर साहू सहित 3-4 लोगों के हाथ में धारदार तलवार जैसे हथियार और कुछ लोगों के हाथो में बेल्ट एवं डंडे थे जिससे वे हाथ घुसा, बेल्ट एवं डंडे से उन्हे मारने लगे। नारायण साहू ने गाड़ी में चढ़कर चाबी निकाल लिया और रोहित कुमार साहू के दोनों जेब से ?1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) निकाला । उसके बाद उन्होने अपनी दो पहिया वाहन (प्लेटिना) को हाइवा वाहन के सामने खड़ा कर निचे धक्का देकर लोगो के द्वारा तोड़ फोड़ किया एवं जानबूझकर हाइवा के नीचे अपने प्लेटिना वाहन को डाल दिया, जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।

सभी आरोपी द्वारा गंदी-गंदी गालियां देते हुए रोहित साहू व चालक को कह रहे थे कि तुम्हे जान से मार देंगे। उन्होंने पीड़ितों को बुरी तरह से मारा एवं पीटा। दोनों डर कर अपनी जान बचाकर बस्ती की तरफ भागे। रोहित साहू अपने बड़े भाई रामकुमार साहू को मोबाइल से घटना कि सुचना दिया उसके भाई के साथ जाकर थाना मे सूचना देने के बाद थाने के वाहन से थाना के सिपाही के साथ बाजार चौक सरसीवा में लाया गया । यह घटना पुर्व मे रोहित साहू के बड़े भाई रामकुमार साहू के साथ भी 3-4 बार हो चुका है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाना सरसीवां में लिखित आवेदन दिया गया था उक्त सुचना को थाना सरसीवां में थाना प्रभारी को दिया जिसकी सुनवाई नहीं किये जाने तथा थाना प्रभारी द्वारा यह बोला गया है कि छोटा केश बना कर इस घटना को टाल दुगा कहा गया इस पर पीड़ित रोहित साहू द्वारा आरोप लगाया गया तथा चोट लगने पर मु आवजा भी कराया गया था परन्तु अभी तक इस घटना पर कार्यवाही नही होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्यान कि गुहार लगाये ।

सोमनापुर नया में उड़नदस्ता टीम का औचक निरीक्षण, परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न

कबीरधाम /मूक पत्रिका

विकासखंड पंडरिया अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल सोमनापुर नया में बीते मंगलवार को हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2026 के तहत अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान उड़नदस्ता टीम ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया।उड़नदस्ता दल में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया एम. के. गुप्ता, विकासखंड क्रीड़ा अधिकारी अश्वनी चंद्राकर, राजीव श्रीवास्तव एवं श्रीमती नीलम श्रीवास्तव शामिल रहे। टीम ने सुबह 10:25 बजे से 10:40 बजे तक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही थी। विद्यालय में कुल 109 विद्यार्थियों का पंजीयन है, जिनमें सभी परीक्षार्थी उपस्थित रहे। केंद्र में बिजली, पानी एवं बैठक व्यवस्था तीन कमरों में सुव्यवस्थित रूप से की गई थी तथा सभी कक्षों में पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षक तैनात थे।उड़नदस्ता टीम ने प्रश्न पत्र वितरण रजिस्टर, उत्तर पुस्तिका रजिस्टर एवं पर्यवेक्षक ड्यूटी रजिस्टर का भी बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की नकल सामग्री नहीं पाई गई तथा सभी छात्र-छात्राएं अनुशासन में परीक्षा देते हुए पाए गए। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष विजय लाल पर्ची, सहायक केंद्राध्यक्ष महेंद्र कुमार कंठले, योगेश कुमार गुरुदीवान, पर्यवेक्षक महेश जायसवाल, कार्तिक राम खूटे, प्रताप सिंह राठौर, श्रीमती मनीषा मार्को, श्रीमती प्रतिमा शर्मा एवं कु. सरिता कंवर सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।

रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत :

नावापारा छोटे में नारियल के साथ गेंदा, अरबी और धनिया की क्रॉस फॉर्मिंग से शुरू हुई आमदनी..

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

सरिया तहसील के बुदबुदा ग्राम पंचायत अंतर्गत नावापारा (छोटे) गांव में एक अलग ही मिसाल देखने को मिल रही है। दिसंबर 2023 में असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर पद से रिटायर हुए शिव प्रसाद प्रधान ने आराम की राह नहीं चुनी, बल्कि खेती में नया प्रयोग शुरू कर दिया।करीब 3 एकड़ जमीन पर नारियल की खेती कर वे क्षेत्र में नई सोच को जन्म दे रहे हैं। उनके साथ बेटे सानंद प्रधान भी कंधे से कंधा मिलाकर खेत को आधुनिक फार्म हाउस के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं।

उड़ीसा से मिली प्रेरणा, कोंडागांव से आए पौधे-दरअसल बीते दिनों ओडिशा यात्रा के दौरान पुरी में नारियल के खेत देखकर शिव प्रसाद के मन में यह विचार आया। वहां किसानों से बातचीत में पता चला कि नारियल से स्थायी और अच्छी आमदनी हो रही है। बस यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि गांव में कुछ अलग करना है।जिसके बाद नारियल के लगभग 250 पौधे नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव से लाए गए। नवंबर माह में रोपण किया गया। मिट्टी और जलवायु को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक पद्धति से पौधों की देखभाल की जा रही है।

क्रॉस फॉर्मिंग से शुरू हुई आमदनी-नारियल के पौधों के बीच खाली जगह को खाली नहीं छोड़ा गया। कृषि और उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन लेकर क्रॉस फॉर्मिंग की शुरुआत की गई। संतोषिनी गुप्ता (आश्वह) की सलाह पर गेंदा, अरबी, टमाटर और धनिया की खेती साथ में की गई। नारियल रोपण के एक माह बाद गेंदा और अरबी लगाई गई। आज गेंदा फूल से आमदनी शुरू हो चुकी है। यानी नारियल से लंबी अवधि की आय की तैयारी के साथ-साथ बीच की फसलों से त्वरित लाभ भी मिल रहा है। यह मॉडल किसानों के लिए प्रेरक बनता जा रहा है।

युवाओं के लिए प्रेरणा-गांव और आसपास के कई युवा इस प्रयोग को देखने खेत तक पहुंच रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ नई फसलें जोड़कर आय बढ़ाई जा सकती है, यह संदेश शिव प्रसाद दे रहे हैं। उ नका मानना है कि शुरुआत में सही देखभाल और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए तो नारियल आने वाले वर्षों में स्थायी आय का मजबूत स्रोत बन सकता है।

कृषि विभाग ने किया निरीक्षण-बीते शुक्रवार को कृषि विभाग के उप संचालक आशुतोष श्रीवास्तव अधिकारी कर्मचारियों की टीम के साथ खेत पहुंचे और निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने इस पहल को सराहा और इसे क्षेत्र के लिए सकारात्मक प्रयोग बताया।

नई सोच, नई राह-रिटायरमेंट के बाद जहां अधिकतर लोग विश्राम चुनते हैं, वहीं शिव प्रसाद ने खेती को नए नजरिए से अपनाया है। नारियल के साथ गेंदा, अरबी, टमाटर और धनिया की क्रॉस फॉर्मिंग से यह साफ हो गया है कि अगर सोच बदली जाए तो खेती भी कमाई का मजबूत जरिया बन सकती है। नावापारा छोटे का यह खेत अब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि युवाओं के लिए सीखने का केंद्र बनता जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

Galaxy AI ने मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम का किया विस्तार; यूज़र्स को मिलेंगे अधिक विकल्प और बेहतर नियंत्रण

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी AI का विस्तार करते हुए मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य यूज़र्स को अधिक विकल्प, और बेहतर नियंत्रण देना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्य कम मेहनत और अधिक स्वाभाविक तरीके से पूरे कर सकें।

कंपनी के अनुसार, अब लोग अलग-अलग कामों के लिए कई तरह के AI एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से लगभग 8 यूज़र्स दो या उससे अधिक AI एजेंट्स पर निर्भर हैं। इसी बदलाव को देखते हुए, सैमसंग गैलेक्सी AI को इस तरह विकसित कर रहा है कि यूज़र अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इंटीग्रेटेड एआई अनुभवों को चुन सकें। गैलेक्सी AI को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर गहराई से जोड़ा गया है। यह केवल किसी एक ऐप तक सीमित रहने के बजाय पूरे डिवाइस के सिस्टम लेवल पर काम करता है। यह यूज़र की जरूरतों को समझते हुए ज्यादा स्वाभाविक और सरल इंटरैक्शन सुनिश्चित करता है। इससे बार-बार ऐप बदलने या एक ही कमांड को बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती और एआई बैकग्राउंड में बिना किसी रुकावट के काम करता रहता है। साथ ही, सैमसंग अपने अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए परप्लेक्सिटी जैसी सहायक सेवाओं को भी जोड़ रहा है, ताकि पूरा गैलेक्सी इकोसिस्टम एक जैसा और सहज महसूस हो। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस के प्रेसिडेंट और आर एंड डी हेड, वॉन-जून चोई ने कहा, हम एक खुले और समावेशी एआई इकोसिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो यूज़र्स को जटिल कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अधिक विकल्प और

नियंत्रण दे। गैलेक्सी AI एक ऑर्केस्ट्रेटर (सूत्रधार) की तरह काम करता है, जो विभिन्न एआई क्षमताओं को जोड़कर एक सहज और एकीकृत अनुभव प्रदान करता है। इस विस्तार के तहत, सैमसंग आगामी फ्लैगशिप गैलेक्सी डिवाइसेज़ में परप्लेक्सिटी को एक अतिरिक्त AI एजेंट के रूप में पेश करेगा। यूज़र "Hey Plex" (हे प्लेक्स) वॉयस कमांड या साइड बटन को दबाकर सीधे इसका उपयोग कर सकेंगे। परप्लेक्सिटी को सैमसंग नोट्स, क्लॉक, गैलरी, रिमाइंडर और कैलेंडर जैसे ऐप्स में गहराई से जोड़ा जाएगा। इससे यूज़र्स बिना अलग-अलग ऐप्स को मैन्युअल रूप से मैनेज किए, मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो को आसानी से पूरा कर सकेंगे। सैमसंग अपने एआई इकोसिस्टम को भरोसेमंद भागीदारों के साथ मिलकर लगातार बढ़ाता रहेगा। कंपनी जल्द ही इस सुविधा से जुड़े डिवाइस और अन्य अनुभवों की जानकारी साझा करेगी।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने RuPay ऑन-द-गो कार्ड्स के लिए इंस्टैंट NFC-बेस्ड बैलेंस अपडेट लॉन्च किया

आज एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने RuPay NCMC ऑन-द-गो कार्ड्स पर इंस्टैंट ह्स्नष्ट-बेस्ड बैलेंस अपडेट फीचर पेश किया। अब ग्राहक अपने कार्ड का बैलेंस ह्स्नष्ट पॉवर्ड एन्ड्रॉयड स्मार्टफोन परकार्डकोटैप करके तुरंत चेक और अपडेट कर सकते हैं, जिससे मेट्रो स्टेशन के कियोस्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी औरएकसहज, पूरी तरह से डिजिटल यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

यह फीचर एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कुछ महीने पहले पेश करके इसके वास्तविक उपयोग की जानकारी एकत्रित की थी तथा ग्राहकों का फीडबैक लिया था। इस पायलट में ग्राहकों ने इसे बहुत पसंद किया तथा इसे काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इससे साबित हो गया कि यह फीचर यूज़र्स के लिए काफी दैनिक उपयोगिता रखता है। यूज़र्स का पॉज़िटिव फीडबैक मिलने के बाद अब बैंक इसे अपने RuPay ऑन-द-गो कार्ड्स के सभी यूज़र्स के लिए लॉन्च कर रहा है। इससुविधाकेसाथ, यात्री एयरटेल थैंक्स ऐप पर अपने बैंक खाते या वॉलेट में लॉगइन करने के बाद, अपनेलिंककिएगए NFC-इनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कार्ड टैप करके अपने कार्ड बैलेंस को रियल टाइम में अपडेट या चेक कर सकते हैं। कार्ड ऑर्डर करने और रिचार्ज करने से लेकर बैलेंस को तुरंत अपडेट या चेक करने तक, पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल, बिना कतार के और बेहद आसान है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर - बिज़नेस ऑपरेशंस, श्री गणेश अनंतनारायणन ने कहा, ''एयरटेल पेमेंट्स बैंक में हम निरंतर ऐसे इनोवेशन करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो दैनिक लेन-देन को और ज्यादा आसान एवं इन्ट्यूटिव बना दे। हमारे पायलट फेज़ में मिली बेहतरीन प्रतिक्रिया से ऑन-द-गो रहते हुए तुरंत बैलेंस अपडेट होने की जरूरत प्रमाणित हो गई। इस लॉन्च के साथ हमें उद्योग का ऐसा पहला सॉल्यूशन पेश करने पर गर्व है, जो ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ाएगा और भारत में डिजिटल पेमेंट एवं मोबिलिटी के परिवेश को मजबूत भी करेगा।'' एयरटेल पेमेंट्स बैंक RuPay ऑन-द-गो कार्ड्स के मुख्य जारीकर्ता बैंकों में से एक है। यह आज तक 5 मिलियन से अधिक कार्ड जारी कर चुका है। यह लॉन्च भारत के ट्रांज़िट परिवेश में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्राहकों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक फाईनेंशियल एवं मोबिलिटी समाधानों का निर्माण करने की बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

रेलवे फाटक के पास अवैध रेत-गिट्टी डंपिंग का खेल माइनिंग विभाग बेखबर?

मूक पत्रिका/रायगढ़ =शहर के हीरापुर रेलवे फाटक के पास सड़क किनारे अवैध रूप से रेत और गिट्टी का बड़े पैमाने पर डंपिंग किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय का आरोप है कि ठेकेदार खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेलवे सरकारी जमीन और सड़क किनारे निर्माण सामग्री जमा कर रहे हैं, जिससे राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह फाटक जब खुलता था तो डंपिंग अंदर तरफ होती थी अब यह सड़क में है ।

स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात ट्रैक्टर-ट्रॉली और हाइवा वाहनों से रेत और गिट्टी लाकर डंप की जा रही है। सुबह होते ही इन्हीं ढेरों से सामग्री की सप्लाई की जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस कारोबार की भनक माइनिंग विभाग को अबतक नहीं हो पाना कई सवालों के घेरे में नज़र आता है।

सड़क सुरक्षा पर खतरा- रेलवे फाटक के पास सड़क किनारे ऊंचे-ऊंचे ढेर लगाए जाने से राहगीरों और वाहन चालकों के आवाजाही से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल उड़ने से आसपास के दुकानदार और निवासी भी प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

राजस्व को नुकसान, नियमों की अनदेखी- खनिज नियमों के अनुसार बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर खनिज सामग्री का भंडारण अवैध है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। इससे शासन को राजस्व की हानि होने की आशंका है।

यदि समय रहते किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया तो यह अवैध कारोबार और भी फैल सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या फिर यह अवैध खेल यूं ही चलता रहेगा।

टूज़ोन सोलर ने छत्तीसगढ़ के बाजार में रखा कदम, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के प्रति अपने संकल्प को किया मजबूत

रायपुर: भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कंपनी 'सनटेक एनर्जी सिस्टम्स' के प्रमुख ब्रांड 'टूज़ोन सोलर' (Truzon Solar) ने छत्तीसगढ़ के लिए 'मेटालोन इंडिया' को अपना 'एक्सक्लूसिव मास्टर डीलर' नियुक्त करने की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ ट्रुज़ोन सोलर ने आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ के बाजार में प्रवेश कर लिया है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत के तेजी से बढ़ते सौर ऊर्जा बाजारों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर सीएसपीडीसीएल के कार्यकारी निदेशक श्री एस. के. गजपाल, टूज़ोन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री भवानी सुरेश, ट्रुज़ोन सोलर के सीईओ श्री जकुला श्रीनिवास और मेटालोन इंडिया की संस्थापक सुश्री सस्मिता कर उपस्थित थी। उनकी सामूहिक उपस्थिति प्रगतिशील शहरी शासन और शाश्वत ऊर्जा समाधानों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, जो भविष्य के शहरों के निर्माण में स्वच्छ ऊर्जा के महत्व पर जोर देती है।

कंपनी व्दारा उठाए गए इस रणनीतिक कदम के महत्व को रेखांकित करते हुए टूज़ोन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक भवानी सुरेश ने कहा, 'छत्तीसगढ़ में मेटालोन के साथ यह साझेदारी केवल व्यावसायिक विस्तार तक सीमित नहीं है; बल्कि यह छत्तीसगढ़ में एक लचीली और भविष्योन्मुखी अक्षय ऊर्जा आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह विस्तार केवल दायरे को बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि संबंधित पक्षों के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हुए निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली स्थापित करने के बारे में है।'

टूज़ोन सोलर के सीईओ जक्कुला श्रीनिवास ने कहा, हमने सौर ऊर्जा के विकास में हमेशा अपार संभावनाएं देखी हैं। मेटालोन इंडिया के साथ हमारी साझेदारी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग कौशल और क्षेत्रीय मजबूती का मेल है। साथ ही, हम एक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले सौर बुनियादी ढांचे की नींव रख रहे हैं, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को मजबूती देगा और शाश्वत आर्थिक विकास में योगदान देगा। टूज़ोन सोलर को छत्तीसगढ़ में बाजार की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य अपने मुख्य वितरक के माध्यम से बिक्री और सेवा में भारी वृद्धि करना है।

कर्मियों को दी गई ई-ऑफिस, ईएचआरएमएस, स्पैरो व आईगॉट की ट्रेनिंग

मूक पत्रिका/सारंगढ़ बिलाईगढ़, 24 फ़रवरी 2026/ डिजिटल कार्य प्रणाली के सुचारु संचालन और डिजिटल कार्य कुशलता के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिला पंचायत के सभाकक्ष में ई- ऑफिस, ईएचआरएमएस, स्पैरो पोर्टल एवम आईगॉट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें संबंधित प्रदर्शन के साथ विषयों की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत, एनआईसी द्वारा निर्मित ऑनलाइन फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना फीडबैक डिजिटल रूप में प्रदान किया। यह मॉड्यूल प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सामग्री, प्रशिक्षक की दक्षता एवं समग्र संतुष्टि के मूल्यांकन हेतु विकसित किया गया था।

अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई, सरिया क्षेत्र के विजयपुर में 03 ट्रैक्टर जप्त..

मूक पत्रिका/सारंगढ़ बिलाईगढ़// कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 वाहन ट्रैक्टर पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्रवाई राजस्व और सरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है।

दरअसल बीते दिनों मुख्य सचिव ने जिले में चल रहे अवैध रेत परिवहन को लेकर मीटिंग में नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर संजय कन्नौजे ने जिले के सभी तहसील में राजस्व और पुलिस टीम की टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करने कहा गया था। उसी के परिपालन में आज मंगलवार को सरिया तहसीलदार कोमल साहू और थाना सरिया की टीम द्वारा विजयपुर में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 ट्रैक्टर पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में दिया गया। उक्त ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर ठेंगगुड़ी और 2 सरिया के है। इनका वाहन क्रमांक छत्त13रू2643, छत्त13श्व7957 और एक सोल्ड सोनालिका शामिल है।

यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। सरिया तहसीलदार कोमल साहू ने कहा कि इसी तरह अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर संलिप्त सभी वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगा। उनका कहना है कि इन ट्रैक्टरों के चलते शासन को राजस्व की हानि सहित दुर्घटनाएं भी बढ़ गई है। क्योंकि शराब पीकर और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।

कोटवारों द्वारा संधारित मुसाफिर रजिस्टर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मूक पत्रिका/रायगढ़= रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने ग्राम छाल पहुंचकर पंचायत स्तर की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से कोटवार द्वारा संधारित किए जाने वाले मुसाफिर रजिस्टर का अवलोकन किया और इसे ग्राम स्तरीय प्रशासन का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए इसकी अनिवार्यता और उपयोगिता बताया गया। उल्लेखनीय है कि समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कोटवारों के माध्यम से संधारित होने वाले मुसाफिर, पलायन रजिस्टर को अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए थे।

इसी तारतम्य में कलेक्टर चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम छाल में इस महत्वपूर्ण रजिस्टर की जांच भी की। उन्होंने कहा कि मुसाफिर रजिस्टर केवल औपचारिक अभिलेख न रहकर ग्राम में आने-जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी, गतिविधियों और आपातकालीन समन्वय का आधार होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रजिस्टर में सभी आवश्यक प्रविष्टियां नियमित रूप से की जाएं तथा इसे अद्यतन स्थिति में रखा जाए।

कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में कोटवारों द्वारा मुसाफिर रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक पंजियों का अनिवार्य रूप से संधारण सुनिश्चित कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि यह रजिस्टर ग्रामीण स्तर पर कानून-व्यवस्था, पलायन की निगरानी, बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तथा आपात स्थिति में त्वरित सूचना संप्रेषण के लिए अत्यंत उपयोगी है।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि रजिस्टर में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विद्युत विभाग सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख अधिकारियों के अद्यतन संपर्क नंबर दर्ज हों, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत समन्वय स्थापित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम छाल के पंचायत भवन का भी अवलोकन किया। उन्होंने परिसर में स्थित शासकीय भवनों की स्वच्छता, अभिलेखों की सुव्यवस्था तथा लोक सेवा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन रजिस्टरों की भी समीक्षा की गई और अभिलेखों को व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान धरमजयगढ़ एसडीएम प्रवीण भगत, कृषि एसडीओ प्रभास शंकर सिंह, तहसीलदार लोमस मिरी, जनपद सीईओ एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं तय समय-सीमा में कार्य करें पूर्ण-कलेक्टर

इतवारी बाजार ऑक्सीजोन को 10 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश

नगर निगम क्षेत्र के निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

रायगढ़=शहर के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समय-सीमा की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि समय पर, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी निर्माण हो ताकि रायगढ़ एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में नई पहचान बना सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हों।

कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 1 स्थित दूध डेयरी क्षेत्र में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी आठ महीनों के भीतर ऑक्सीजोन और प्लेग्राउंड का निर्माण पूर्ण कर नागरिकों को समर्पित किया जाए। इसके बाद कलेक्टर ने इतवारी बाजार क्षेत्र में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन का निरीक्षण किया और आगामी दस दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने की सख्त समय-सीमा तय की। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल हरियाली बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि शहरवासियों को स्वच्छ हवा, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण और बच्चों के लिए सुरक्षित खेल परिसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

कलेक्टर ने शहर की जीवनरेखा केलो रिवर के पुनरुद्धार के तहत बनाए जा रहे मरीन ड्राइव का भी गहन निरीक्षण किया। न्यू शनि मंदिर से कायाघाट तक निर्माणाधीन हिस्से की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य सड़क और मरीन ड्राइव का कार्य आगामी बरसात को ध्यान में रखते हुए 30 जून से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसईसीएल साइड में प्रस्तावित मरीन ड्राइव और निर्माणाधीन स्टॉप डैम का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

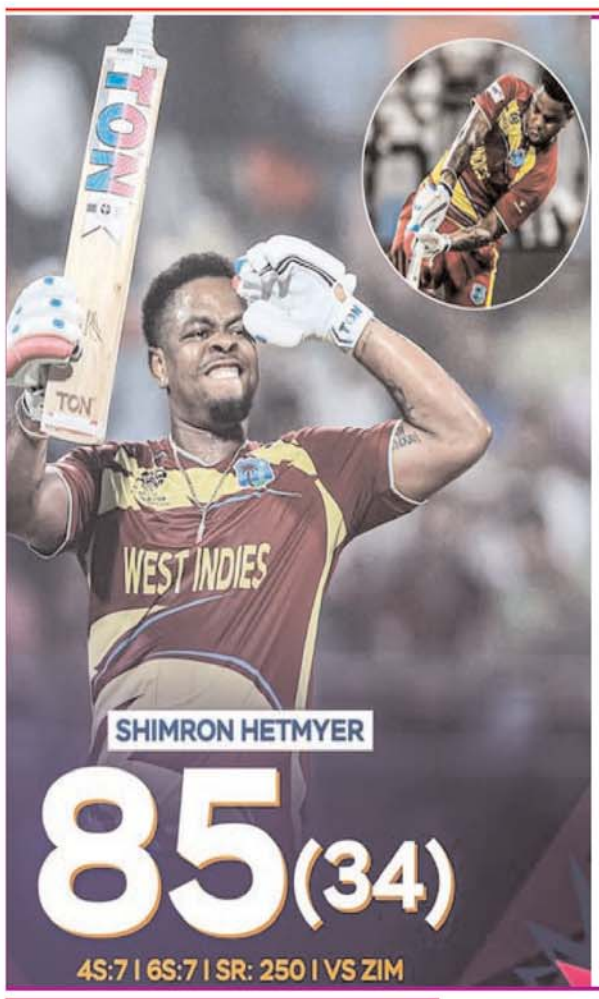

हेटमायर-पॉवेल की फिफ्टी, गुडाकेश मोती को 4 विकेट

वेस्टइंडीज की सुपर-8 में पहल जीत: जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया

मुंबई। शिमरॉन हेटमायर की शानदार बल्लेबाजी के बाद गुडाकेश मोती की अगुआई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 254 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवर में 147 रन पर ऑलआउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने अंत में विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके। यह टी20 में वेस्टइंडीज की रनों के लिहाज से दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 2024 में युगांडा को 134 रनों से हराया था।

अंक तालिका में बड़ा फेरबदल

वेस्टइंडीज की धमाकेदार जीत से ग्रुप-1 की अंक तालिका में बड़ा फेरबदल हुआ है। वेस्टइंडीज की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है और उसका नेट रन रेट +5.350 है। वहीं, दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है जिसका नेट रन रेट +3.800 है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और उसका नेट रन रेट -3.800 है और तीसरे स्थान पर है। मालूम हो कि ग्रुप से शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकेंगी।

जिम्बाब्वे की खराब बल्लेबाजी

बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी बेहद

खराब रही। गुडाकेश मोती और अकील हुसैन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने मैच में पकड़ बना ली। बाएं हाथ के स्पिनर मोती (28 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की पारी पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि उसके चार बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। वेस्टइंडीज के लिए मोती के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन, जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए।

वेस्टइंडीज ने बनाया टी20 विश्व कप का दूसरा सर्वोच्च स्कोर

शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पोवेल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज ने टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इसे गलत साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इस दौरान दो बार हेटमायर के कैच छूटे, लेकिन उन्होंने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। हेटमायर ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में सात छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 85 रन की पारी खेलने के अलावा पोवेल (59 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली।

वेस्टइंडीज की पारी

वेस्टइंडीज ने तीसरे ओवर में ब्रेंडन किंग (09) का विकेट गंवाया जिन्होंने नगारवा की गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा को कैच थमाया। वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में दो विकेट पर 55 रन बनाए। हेटमायर ने नगारवा पर चौके से खाता खोला जबकि मुजरबानी की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। उन्होंने नगारवा के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके जड़े। हेटमायर ने 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। हेटमायर की पारी का अंत क्रेमर ने किया। जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। कप्तान सिकंदर रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।

ब्रीफ न्यूज

हार से उबरकर वापसी करेगी भारतीय टीम

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि टीम टी20 विश्वकप के सुपर-8 के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार से सबक लेकर उतरेगी और जीत के साथ ही टूर्नामेंट में वापसी करेगी। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में 76 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी है। इस हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह भी कठिन हो गयी है हालांकि सैकिया ने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वह हार से उबरेगी अच्छी वापसी करेगी। सोशल मीडिया पर सैकिया ने लिखा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच हार गए पर हम शीघ्र ही वापसी करेंगे।बीसीसीआई सचिव के इस बयान से टीम का हौंसला भी बढ़ेगा। भारतीय टीम को अभी सुपर-8 में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो और मैच खेलने हैं। ऐसे को उसे अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो किसी भी कीमत पर इन दोनों मैचों में बड़ी जीत हासिल करनी होगी हालांकि ये इतना आसान नहीं है। ग्रुप स्तर में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। में दोनों टीमें अजेय रही हैं।अगले दो मैचों में भारतीय टीम को जीत के लिए कुछ बदलाव भी करते हुए फार्म से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को बाहर करना होगा। ऐसे में अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा में से किसी एक को बाहर करते हुए संजू सैमसन की भी टीम में वापसी हो सकती है। अभिषेक अब तक तीन बार अपना खाता भी नहीं खोल पाये और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी केवल 15 रन बना पाये। वहीं तिलक भी पिछले 4 मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल पाये हैं।

वरुण ने अर्शदीप का रिकार्ड तोड़ा लगातार 18 पारियों में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने

अहमदाबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में एक विकेट लेते ही एक नया रिकार्ड बनाया है। वरुण अब लगातार 18 पारियों में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गये हैं। वरुण लगातार 18 पारियों में भारत के लिए विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पीछे छोड़ा। अर्शदीप सिंह ने साल 2024-25 में लगातार 17 पारियों में विकेट लेने का रिकार्ड बनाया था। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 2025-26 के बीच अब तक कुल 18 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इसी सूची में तीसरे नंबर पर पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा है। नेहरा ने साल 2016 में 13 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए थे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 2024-25 में 11 बार ये कारनामा किया था। वरुण का नाम इस सूची में दूसरी बार आया है। इससे पहले उन्होंने साल 2024-25 में 11 बार एक या उससे अधिक विकेट लिए थे।

इंग्लैंड को हराकर शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेगा पाकिस्तान

स्पिनर्स पर रहेगी नजर; कैसा रहेगा मौसम

कोलंबो। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सुपर-8 का रोमांचक मुकाबला आज को पल्लेकेले में खेला जाएगा।पाकिस्तान की नजर इस मुकाबले में जीत के साथ ग्रुप-2 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने पर होंगी। वहीं, श्रीलंका को हराकर इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है।धीमी और स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर आज को जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में आमने-सामने होंगी, तो मुकाबले का केंद्र बिंदु स्पिन गेंदबाज ही रहेंगे। इंग्लैंड की टीम अब तक टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन दो बार की चैंपियन यह टीम अब जीत की राह पर लौट चुकी है। सुपर आठ चरण के अपने पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। इस जीत से उसका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ और वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।

श्रीलंका के खिलाफ जीत से बढ़ा इंग्लैंड का आत्मविश्वास

श्रीलंका के खिलाफ कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए इंग्लैंड ने परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन किया। टीम के स्पिनरों ने शानदार गेंदबाजी की, जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी अहम योगदान दिया। लेग स्पिनर आदिल रशीद और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन को भी विकेट मिले। विल जैक्स ने प्रभावी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उपयोगी पारियां खेलकर टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है।

पाकिस्तान को हर हाल में जीतना होगा मुकाबला

दूसरी ओर, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सुपर आठ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। अब उसे सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अपने दोनों शेष मैच जीतने होंगे। पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक, सईम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे सक्षम स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। खासकर अच्छे स्पिनरों के खिलाफ टीम के बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे हैं।पल्लेकेले में नमी का स्तर अधिक रहने की उम्मीद है, जो लगभग 78 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि, शाम के समय बारिश की संभावना घटकर करीब 13 प्रतिशत रह जाएगी। सभी संकेतों को देखते हुए, पल्लेकेले में पाकिस्तान और इंग्लैंडके बीच पूरा मैच बिना किसी बड़ी रुकावट के संपन्न होने की उम्मीद है।

कैसा रहेगा मौसम

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के लिए मौसम का पूर्वानुमान काफी अनुकूल नजर आ रहा है। आज को अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और बारिश की केवल 25 प्रतिशत आशंका जताई गई है। वहीं, आंधी-तूफान की संभावना लगभग 6 प्रतिशत बताई गई है।

सुपर-8 मुकाबले के लिए दोनों टीमें

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बेंटोन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जैमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग, ल्यूक वुड।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

पूर्व महिला कप्तान ने इस पुरुष तेज गेंदबाज पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

बांग्लादेश। बीसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मोंजुरुल इस्लाम को बीसीबी के तहत क्रिकेट से जुड़ी किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया है। इस्लाम 2020 में बांग्लादेश की महिला टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हुए थे।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व महिला कप्तान जहांआरा आलम द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई की है। जहांआरा ने पूर्व चीफ सेलेक्टर और तेज गेंदबाज मंजरुल इस्लाम पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।

बोर्ड ने जांच के बाद लगाया बैन

मोंजुरुल इस्लाम पर लगा बैन

बीसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मोंजुरुल इस्लाम को बीसीबी के तहत क्रिकेट से जुड़ी किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया है। इस्लाम 2020 में बांग्लादेश की महिला टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हुए थे। रविवार को ढाका में बीसीबी की बोर्ड मीटिंग हुई जिसके बाद बयान जारी कर बताया गया कि इस्लाम को भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट में किसी भी तरह की भूमिका के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है।

बीसीबी का बयान

बीसीबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'बांग्लादेश की राष्ट्रीय महिला टीम की पूर्व कप्तान जहांआरा आलम की शिकायत की जांच के लिए बीसीबी की तरफ से गठित स्वतंत्र जांच समिति के नतीजों के आधार पर बोर्ड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर मोंजुरुल इस्लाम को बीसीबी के तहत किसी भी तरह की क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर तरह की भूमिका से प्रतिबंधित किया जाता है।

रियो ओपन टेनिस: अर्जेंटीना के टोमास मार्टिन एचवेरी ने चिली के एलेजांद्रो तबिलो को हराया

दिल्ली। अर्जेंटीना के टोमास मार्टिन एचवेरी ने ब्राजील में रियो ओपन टेनिस के फाइनल में चिली के एलेजांद्रो तबिलो को 3-6, 7-6(3), 6-4 से हराकर अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता। बारिश के कारण उनका सेमीफाइनल मैच स्थगित हो गया था, इस कारण उन्हें एक ही दिन में दो मैच खेलने पड़े। 26 वर्षीय एचवेरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करियर का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। तीन फाइनल में उपविजेता रहने के बाद यह उनका पहला एटीपी खिताब है।

दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, वनडे-टेस्ट मैचों की होगी सीरीज; जानें कार्यक्रम

मुंबई। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा सीजन के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा भी शामिल है। दोनों टीमों के बीच सितंबर-अक्तूबर में वनडे और टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वर्ष सितंबर-अक्तूबर के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। इस दौरान तीन वनडे और इतने ही टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। ऐसे में यह बॉल-टैंपरिंग प्रकरण के बाद ऑस्ट्रेलिया का पहला दक्षिण अफ्रीकी दौरा होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के मौजूदा चक्र के लिहाज से भी यह सीरीज काफी अहम होगी।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने जारी किया शेड्यूल

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2026-27 सीजन के लिए अपना इंटरनेशनल शेड्यूल जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया का यह टूर सितंबर में तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से शुरू होगा। इस सीरीज का पहला मैच 24 सितंबर को डरबन में खेला जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर को जोहानिसबर्ग दूसरे मैच की मेजबानी करेगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 30 सितंबर को पोचेफस्ट्रूम में आयोजित होगा।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम

तिथि	मैच	स्थान
पहला वनडे	24 सितंबर	डरबन
दूसरा वनडे	27 सितंबर	जोहानिसबर्ग
तीसरा वनडे	30 सितंबर	पोचेफस्ट्रूम

टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम

तिथि	मैच	स्थान
पहला टेस्ट	9-13 अक्तूबर	डरबन
दूसरा टेस्ट	18-22 अक्तूबर	गकेबरहा
तीसरा टेस्ट	27-31 अक्तूबर	केपटाउन

प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलते हुए आर्सेनल और टोटेनहम हार्सपुर के खिलाड़ी

सभी मैच खेलेंगे या नहीं, टूर्नामेंट के समय तय किया जाएगा

IPL 2026- धोनी CSK के लिए कुछ मैच खेलेंगे

मुंबई। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। धोनी इस साल जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे। फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट ने उनकी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वे कुछ मैचों से ब्रेक ले सकते हैं।

सीएसके के एक टॉप सोर्स के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, 'हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि धोनी चेन्नई आ रहे हैं और उन्होंने इस सीजन के लिए अपनी उपलब्धता स्पष्ट कर दी है। वे सभी मैच खेलेंगे या नहीं, यह फिलहाल कहना मुश्किल है।'

संजू सैमसन के आने से विकेटकीपिंग का विकल्प खुला

इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में संजू सैमसन की एंट्री हुई है। सैमसन के आने से टीम के पास विकेटकीपिंग के मजबूत विकल्प मौजूद हैं। मैनेजमेंट की योजना है कि जिन मैचों में धोनी को आराम दिया जाएगा, वहां सैमसन ग्लव्ज संभालेंगे।

धोनी पिछले कुछ समय से घुटने और पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं। ऐसे में 45 की उम्र में हर मैच में विकेटकीपिंग करना उनके शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संजू के अलावा टीम में टीम में उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा विकेटकीपर के तौर पर शामिल है। कार्तिक को फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्हें शिवम दुबे के साथ फिनिशर के रूप में तैयार किया जा रहा है।

चेपॉक के हर होम गेम में दिखने की उम्मीद

धोनी का चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम और वहां के फैंस के साथ एक इमोशनल रिश्ता है। सूत्रों का कहना है कि धोनी कोशिश करेंगे कि वे चेन्नई में होने वाले सभी होम मैच जरूर खेलें। फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी वैसी ही है और उनके मैदान पर कदम रखते ही पूरा स्टेडियम 'धोनी-धोनी' के नारों से गूंज उठता है। टीम में उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा जैसे युवा विकेटकीपर भी शामिल हैं, जो बैकअप के तौर पर तैयार रहेंगे।

इम्पैक्ट प्लेयर रूल का मिल सकता है फायदा

पिछले सीजन की तरह इस बार भी धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आ सकते हैं। वे निचले क्रम में आकर फिनिशर की भूमिका निभाते रहे हैं। फिट रहने के लिए उन्होंने अपनी बैटिंग को कुछ खास ओवरों तक ही सीमित रखा है। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि धोनी मैदान पर रहें, भले ही वे सिर्फ आखिरी के कुछ ओवरों में बैटिंग करें या मेंटर की तरह टीम को गाइड करें।

आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान

धोनी आईपीएलमें 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 226 मैचों में कप्तानी की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 158 मैचों में कप्तानी की है।

समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों, विभाग्य योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई

विभागीय योजनाओं के अपेक्षित प्रगति में कमी पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार ... कलेक्टर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारियों की समय सीमा ली । बैठक में प्रशासनिक कसावट लाने को लेकर एक अहम संकेत देखने को मिला । कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं की अपेक्षित प्रगति निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपेक्षित प्रगति में कमी लक्ष्य का सीधा असर आम जनता तक पहुँचने वाले लाभों पर पड़ता है। ?उन्होंने इस स्थिति अधिकारियों को जवाबदेही के साथ दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाने निर्देशित की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने मुख्य पाया कि कई महत्वपूर्ण विभागों में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर है। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने

निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रकरणों के निराकरण और विभागीय लक्ष्य की पूर्ति में ?समय-सीमा का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए।

आवंटित राशि का असर धरातल पर दिखे

कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है ?बजट का सही उपयोग होना चाहिए। आवंटित राशि का धरातल पर असर दिखनी चाहिए। ?बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को चेतावनी देते गाइडलाइन्स का पालन जवाबदारी पूर्वक करने कहा।

प्रदर्शन में सुधार करने केनिर्देश

कलेक्टर ने लक्ष्य आधारित कार्ययोजना को तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने कहा।सभी अधिकारियों को एक कार्ययोजना निर्धारित करने कहा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे पिछड़े हुए लक्ष्यों की भरपाई कैसे करेंगे। कलेक्टर ने 'फील्ड विजिट' में बढ़ोतरी करने भी कहा। उन्होंने कहा कि ?अधिकारी केवल ऑफिस तक सीमित ना रहें, फील्ड विजिट कर योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करें । उन्हें सप्ताह में अनिवार्य रूप से फील्ड में जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन करना कहा।

प्रदर्शन के आधार पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने कहा कि प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ÷यदि आगामी समीक्षा बैठक तक प्रगति में सुधार नहीं दिखा, तो संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने, वेतन वृद्धि रोकने जैसी कार्यवाही की जाएगी। प्रतिकूल प्रविष्टि देने की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभागवार समीक्षा में कमियों को दूर करने के निर्देश

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कमियों को दूर कर सारगर्भित रूप से निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने कहा। कलेक्टर ने लोक निर्माण को अधूरी सड़कों व स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र टेंडर कर मानसून से पहले पूर्ण करने कहा। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड वितरण और टीकाकरण के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ण करने निर्देशित की।

आम आदमी के लिए बजट या सिर्फ आंकड़ों का खेल, सभी वर्गों में हताशा : परमेश्वर पात्रे

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना तीसरा बजट पेश करते हुए इसे ÷विकासोन्मुख÷ और ÷ऐतिहासिक÷ बताया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत और बजट दस्तावेज़ों का सूक्ष्म अध्ययन कुछ और ही कहानी बयां करता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (हस्द्ध) की जिला उपाध्यक्ष बेमेतरा परमेश्वर पात्रे ने बजट पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा, बल्कि बड़े-बड़े आंकड़ों की चमक तक सीमित प्रतीत होता है।

बड़ा आकार, पर ज़मीन पर असर कहां?-सरकार ने इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बजट का आकार बढ़ाना ही विकास की गारंटी है? योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ की स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। आम नागरिकों–विशेषकर बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूर वर्ग–को ठोस राहत का इंतजार अब भी है।

बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस

रोडमैप नहीं-राज्य में बेरोजगारी लगातार एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। बजट भाषण में कौशल विकास और स्वरोजगार की बातें जरूर कही गई, लेकिन बड़े पैमाने पर नई सरकारी भर्तियों या रोजगार सृजन की ठोस योजना का अभाव साफ नजर आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को उम्मीद थी कि इस बार कोई निर्णायक घोषणा होगी, लेकिन उन्हें फिर निराशा हाथ लगी।

किसानों के लिए घोषणाएं ज्यादा, राहत कम-किसानों की आय दोगुनी करने का वादा वर्षों से दोहराया जा रहा है। इस बजट में कृषि के लिए प्रावधान तो किए गए हैं, परंतु लागत घटाने, समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी या कर्ज राहत जैसे सीधे लाभकारी कदमों पर स्पष्टता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में यह भावना बन रही है कि घोषणाएं ज्यादा हैं, लेकिन जेब तक पहुंचने वाला लाभ सीमित है।

मजदूर और असंगठित वर्ग फिर हाशिए पर-महंगाई की मार झेल रहे मजदूर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और न्यूनतम मजदूरी में ठोस सुधार की उम्मीद थी। लेकिन बजट में इस वर्ग के लिए कोई बड़ा या निर्णायक कदम नजर नहीं आता। दैनिक आय पर निर्भर वर्ग के लिए यह बजट राहत की बजाय औपचारिकता जैसा प्रतीत होता है।

कर्मचारियों की उम्मीदें भी अधूरी-राज्य के कर्मचारी वेतनमान, भत्तों और लंबित मांगों को लेकर आशान्वित थे। बजट में इन मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय या घोषणा का अभाव कर्मचारियों में असंतोष को बढ़ा सकता है। प्रशासनिक वर्ग में भी निराशा की चर्चा है।

सवालों के घेरे में ÷विकास÷-सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन आलोचकों का मानना है कि केवल आंकड़ों का विस्तार विकास का प्रमाण नहीं होता। असली कसौटी यह है कि संसाधनों का वितरण किस प्राथमिकता के आधार पर और किस वर्ग के हित में किया गया है।

बेमेतरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के द्वारा बेमेतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय उद्घाटन नगर क्षेत्र बेमेतरा में किया गया है उद्घाटन अवसर पर बेमेतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मिथलेश वर्मा एवं शहर अध्यक्ष श्रीमति रश्मि मिश्रा ने अपना पदभार भी ग्रहण किया साथ ही साथ उद्घाटन कार्यक्रम में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया तथा बेमेतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को उनके पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर जिला कांग्रेस

कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें विशेष कर किसानों तथा गरीब वर्ग की समस्याओं को हमें गंभीरता के साथ हल करने के लिए आगे बढ़ना है जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी की आम जनता के बीच हमें अपनी पैठ बनानी है लोगों को आज की परस्थिति में सिर्फ कांग्रेस से उम्मीदें रह गई है और हम सभी को आम जनता की उम्मीद पर खरे उतरे इस अवसर पर सुरेंद्र तिवारी टी आर जनार्दन प्राणीश चौबे ललित विश्वकर्मा दिनेश पटेल प्रांजल तिवारी हरीश साहू शशि प्रभा गायकवाड बाल कुमारी ध्रुव रीता पांडे राजू साहू सुमित विवेक राजपूत शकुंतला साहू राजेंद्र वर्मा योगेश जांगड़े हरि साहू जनता साहू टोकेश्वर साहू नवीन ताम्रकार मनोज शर्मा प्रकाश ठाकुर योगिता साहू रीना मिथलेश वर्मा रमा साहू लुकेश वर्मा सुमन गोस्वामी घाशी वर्मा अजय राज सेन अमित वर्मा शिव वर्मा शुभम गंधर्व मोहित वर्मा बहल वर्मा सुनील नामदेव जावेद खान संजय वर्मा कमल साहू जय प्रकाश राज निलेश वैष्णव किशुन वर्मा राजकुमार बंजारे सुखराम वर्मा चितरेन वर्मा अनिल दुबे निलेश ठाकुर मनीष ठाकुर राजू रजक कमल पुरी गोस्वामी मूरत राम मांडवी अशोक जायसवाल घनश्याम देवांगन रोहित साहू मनोज साहू राजू वर्मा द्वारका वर्मा युवराज योगी साहू प्रमोद वर्मा महेश वर्मा रोहित साहू टिकेंद्र बंजारे युवराज सिंह मनीष सिंह बंजारे दिनेश यादव अर्जुन साहू टोमन पाटिल देवचरण पांडे चेतन पांडेय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

मानदेय वृद्धि सहित 8 मांगों पर महिलाओं का कलमबंद आंदोलन, मांगें पूरी होने तक काम बंद रखने का ऐलान

कांकेर/मूक पत्रिका

एनआरएलएम बिहान सक्रिय महिला संघ (सीआरपी) एवं कृषि सखी-पशु सखी संघ (ढ्ढञ्जष्ट) से जुड़ी महिलाओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 फरवरी से संपूर्ण काम बंद कर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में कई बार आवेदन और आंदोलन के माध्यम से मांगें रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि उनसे व्यापक कार्य लिया जाता है, जबकि मानदेय मात्र 1910 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। संगठन ने मानदेय को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने, न्यूनतम वेतन

अधिनियम के अनुसार भुगतान करने, लंबित राशि जारी करने, मोबाइल व यात्रा भत्ता देने, मानदेय सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने तथा नियुक्ति पत्र जारी कर नियमितीकरण की मांग की है। महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक काम बंद जारी रहेगा।

सुकमा में वेतन न मिलने से कर्मचारी की मौत पर बसपा का आक्रोश, कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

सुकमा/मूक पत्रिका

नगरपालिका परिषद सुकमा में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी सुकमा इकाई ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यंत शर्मनाक बताया है। पार्टी का आरोप है कि लंबे समय से वेतन लंबित रहने के कारण कर्मचारी गोविंद स्वामी को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बसपा नेताओं ने कहा कि यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है और इससे कर्मचारियों के परिवारों पर गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। पार्टी ने नगरपालिका परिषद सुकमा से तत्काल बकाया वेतन जारी करने की मांग की है, ताकि अन्य कर्मचारियों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। बहुजन समाज पार्टी सुकमा के जिला अध्यक्ष

सोलोमन गांडा ने बताया कि इस गंभीर मामले को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को न्याय दिलाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। बसपा ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द निर्णय लेगा और कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगा।

नवागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंधक बनाकर मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला बेमेतरा के थाना नवागढ़ पुलिस ने अश्लील गाली-गलौज, जातिसूचक अपमान, बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला? प्रार्थी अक्षय कुमार धिवरे (29 वर्ष), निवासी ग्राम पेण्ड्री, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा ने 28 दिसंबर 2025 को थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे उनके भाई सूर्यदेव धिवरे और भांजा टेकचंद टंडन के साथ आरोपियों ने लाठी-डंडे और रॉड से मारपीट की।बताया गया कि पहले जैतपुरी तालाब में मिट्टी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। बाद में गोढ़ीकला में खाना खाने के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते

हुए हमला किया गया। आरोप है कि मारपीट के बाद पीड़ितों को जबरन विवादित जमीन पर ले जाकर 2-3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया तथा दोबारा गांव में दिखने पर जान से मारने की धमकी दी गई।शिकायत में यह भी उल्लेख है कि दोनों पक्षों के पास जेसीबी, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर होने के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या द्वेष के चलते घटना को अंजाम दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई -घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस (अजाक) राजेश कुमार झा के नेतृत्व में थाना प्रभारी उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव व पुलिस स्टाफ ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया।

गिरफ्तार आरोपी-पुलिस ने निम्न आरोपियों को 23 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया–नारायण वर्मा (48 वर्ष)चेतन सिंह राजपूत (27 वर्ष)जलेश्वर सिंह राजपूत (28 वर्ष)कुलदीप वर्मा (24 वर्ष)पूनाराम (53 वर्ष)झम्मन कुमार राजपूत (24 वर्ष)सभी आरोपी जिला बेमेतरा के विभिन्न ग्रामों के निवासी हैं। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका- इस संपूर्ण कार्रवाई में डीएसपी (अजाक) राजेश कुमार झा, थाना प्रभारी नवागढ़ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक गोपाल अधीक्षक हरीश कुमार यादव के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। एसडीओपी भूषण एक्का और डीएसपी ध्रुव, आरक्षक राजेंद्र साहू, राहुल दुबे सहित समस्त पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शालेय शिक्षक संघ ने संयुक्त संचालक बस्तर संभाग को सौंपा ज्ञापन

काउंसलिंग प्रक्रिया में संशोधन सहित बस्तर की परिस्थितियों के अनुरूप नीति बनाने की मांग

बीजापुर। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ, बीजापुर इकाई ने शिक्षक एलबी संवर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव एवं संचालक के नाम संयुक्त संचालक, शिक्षा बस्तर संभाग को ज्ञापन सौंपा।संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नवपदस्थ संयुक्त संचालक एच.आर. सोम से शिष्टाचार भेंट कर पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए स्वागत किया। संभागीय प्रवक्ता एवं जिला सचिव कैलाश रामटेके के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में 13 फरवरी 2026 को जारी नए राजपत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।संघ ने कहा कि नया राजपत्र शिक्षक एलबी संवर्ग के हितों की अनदेखी करता है, इसलिए इसे अस्वीकार्य माना गया है। पिछले वर्षों से पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है, किंतु बस्तर संभाग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया।ज्ञापन में मांग की गई है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षकों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए। पंचायत शिक्षक भर्ती के दौरान सुरक्षा कारणों से ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय में पदस्थ शिक्षकों को भी यथावत प्राथमिकता देने की बात कही गई है। संघ ने गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों तथा पति-पत्नी प्रकरण वाले मामलों में भी काउंसलिंग में प्राथमिकता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। साथ ही संगठन के ब्लॉक एवं जिला पदाधिकारियों को ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय के समीप पदस्थ करने का आग्रह किया गया।संयुक्त संचालक श्री सोम ने प्रतिनिधिमंडल को नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

दंतेवाड़ा में 'जीवनदायिनी 108' बनी मौत का पहिया!

फर्जी केस, खटारा एम्बुलेंस और कर्मचारियों पर अत्याचार के आरोपों से घिरी आपात सेवा

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

नक्सल प्रभावित और संवेदनशील माने जाने वाले जिले दंतेवाड़ा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के रूप में संचालित 108 एम्बुलेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जीवन बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सेवा अब कथित लापरवाही, फर्जीवाड़े और कर्मचारियों के शोषण के आरोपों के कारण विवादों में है। कर्मचारियों ने संचालन कर रही कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

खटारा गाड़ियों से कैसे बचेगी जान?-सूत्रों के अनुसार जिले में संचालित अधिकांश एम्बुलेंस 3 से 4 लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं और उनकी स्थिति जर्जर बताई जा रही है। कई वाहन महीनों से गैराज में खड़े हैं, लेकिन कागजों में उनकी मरम्मत दर्शाकर भुगतान निकाले जाने के आरोप हैं। जमीनी स्तर पर कई एम्बुलेंस में सायरन बंद, हेडलाइट खराब, मरीज केबिन में रोशनी की व्यवस्था ठप तथा जीवनरक्षक दवाइयों और आवश्यक उपकरणों की कमी जैसी गंभीर खामियां बताई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नक्सल क्षेत्र में क्या मरीजों की जिंदगी जोखिम में डाली जा रही है?

कर्मचारियों पर कार्रवाई, सुधार पर नहीं ध्यान-ईएमटी और पायलटों का आरोप है कि वाहन खराब होने की स्थिति में मेंटेनेंस दुरुस्त करने के बजाय कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जाती है। ÷नो वर्क नो पेमेंट÷ के नाम पर वेतन रोके जाने और मानसिक दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा यह भी आरोप है कि अनुभवी पायलटों को हटाकर अप्रशिक्षित टेक्नीशियन से एम्बुलेंस चलवाई जा रही है, जिनके पास न पर्याप्त अनुभव है और न वैध लाइसेंस। इससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

90 केस का लक्ष्य और फर्जीवाड़े का दबाव-कर्मचारियों का कहना है कि प्रत्येक एम्बुलेंस को प्रतिमाह 90 केस का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य पूरा न होने पर फर्जी केस दर्ज कराने का दबाव बनाया जाता है। आरोप है कि पिछले महीनों में बड़ी संख्या में केस कागजों में दर्शाकर सरकारी राशि निकाली गई।

यह आरोप सही हैं, तो यह न केवल वित्तीय अनियमितता है बल्कि आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ भी है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।